▪ वैशाख कृष्णा - 5 ▪ संवत 2082 ▪ वर्ष - 12 ▪ अंक - 259 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शनिवार » 19-04-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 अगर चिकित्सक के मन में संवेदना नहीं तो वह चिकित्सक कहलाने लायक नहीं
6 क्या बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन?
7 'केसरी चैप्टर 2' सिर्फ फिल्म नहीं, एक अधूरा हिसाब और इंसाफ है : अक्षय कुमार

फर्स्ट टेक

दक्षिण नेपाल में बस हादसा, 21 भारतीय घायल

काठमांडू/भाषा। दक्षिणी नेपाल के डांग जिले में शुक्रवार को एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 20 से अधिक भारतीय घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक कालिका कार्की के मुताबिक, भारतीय नंबर प्लेट वाली बस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई थी और नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पोखरा की ओर जा रही थी, तभी ब्रेक फेल होने के कारण एक मोड़ पर यह दीवार से टकरा गई। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना डांग जिले के गढ़वा ग्रामीण नगरपालिका के चिसापानी क्षेत्र में हुई। गढ़वा क्षेत्र पुलिस कार्यालय के निरीक्षक कार्की ने बताया कि बस चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, बस में चालक समेत 25 लोग सवार थे। इनमें से 21 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया है।

अफगानों के साथ दुर्व्यवहार के लिए पाक सरकार पर बरसे इमरान

लाहौर/भाषा। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पड़ोसी अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना करते हुये कहा कि मौजूदा अफगानिस्तान विरोधी नीति से देश में केवल आक्रोश और आतंकवाद बढ़ेगा। खान (72) ने बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''अफगान शरणार्थियों के साथ चल रहा व्यवहार शर्मनाक है। सत्ता पर काबिज होने के लिए बेताब सत्तारूढ़ माफिया किसी भी हद तक जा सकता है। मौजूदा अफगानिस्तान विरोधी नीति केवल और अधिक आक्रोश पैदा करेगी तथा आतंकवाद को बढ़ावा देगी।'' पाकिस्तान सरकार वर्तमान में अवैध और बिना दस्तावेज वाले अफगानों को वापस भेज रही है।

जापान के नागानो में भूकंप के झटके

टोक्यो/एजेन्सी। जापान के नागानो प्रान्त में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश की मौसम एजेंसी के अनुसार शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार रात 8:19 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर पांच मापी गयी एवं भूकंप का केन्द्र 10 किलोमीटर की गहरायी पर था। एजेंसी के अनुसार ओमाची, चिकुहोकू गांव और ओगावा गांव के शहरों में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता पांच से कम दर्ज की गयी तथा सुनामी का कोई खतरा नहीं है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ओगावा गांव के कुछ हिस्सों में बिजली गुल होने की सूचना मिली है लेकिन स्थानीय अग्निशमन विभागों ने रात 9:00 बजे तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है।

'महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज असली राष्ट्रीय नायक हैं, औरंगजेब नहीं'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र)/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रीय नायक हैं, न कि मुगल शासक औरंगजेब।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित समारोह में सिंह ने कहा कि जो लोग औरंगजेब या बाबर का महिमामंडन करते हैं, वे देश के मुसलमानों का अपमान करते हैं।

सिंह ने कहा, ''महाराणा प्रताप साहस और देशभक्ति के प्रतीक थे... छत्रपति शिवाजी महाराज ने विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए महाराणा प्रताप से प्रेरणा ली थी।''

■ जो लोग मानते हैं कि औरंगजेब एक नायक था, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़नी चाहिए, जिन्होंने लिखा था कि मुगल बादशाह एक क्रूर, कट्टरपंथी शासक था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि स्वतंत्रता के बाद वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज दोनों को उचित श्रेय नहीं दिया, बल्कि औरंगजेब का महिमामंडन किया। उन्होंने कहा, ''जो लोग मानते हैं कि औरंगजेब एक नायक था, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़नी चाहिए, जिन्होंने लिखा था कि मुगल बादशाह एक क्रूर, कट्टरपंथी शासक था।''

सिंह ने कहा कि ऐसा व्यक्ति नायक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ''दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया और औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। दारा शिकोह सभी धर्मों का सम्मान करते थे।''

सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और मुगल सम्राट अकबर के प्रभुत्व को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अपनी अनुकरणीय वीरता के अलावा महाराणा प्रताप ने समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया। उन्होंने कहा, ''आदिवासी और मुसलमान उनकी सेना का हिस्सा थे। हकीम खान सूरी ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए हल्दीघाटी की लड़ाई में अपना जीवन बलिदान कर दिया। एक मुस्लिम युवक शिवाजी महाराज का अंगरक्षक था।''

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुक्ला अगले महीने अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार : जितेंद्र सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अगले महीने 'एक्सिओम-4' मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। यह यात्रा राकेश शर्मा की रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने की ऐतिहासिक यात्रा के चार दशक बाद होगी।

सिंह ने यहां अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कार्यों की समीक्षा के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ''ग्रुप कैप्टन शुक्ला की यात्रा महज एक उड़ान नहीं है - यह एक संकेत है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग में साहस के साथ कदम रख रहा है।''

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने विभिन्न आगामी अंतरिक्ष अभियानों पर एक प्रस्तुति दी।

सिंह ने कहा कि इसरो जून में जीएसएलवी-मार्क 2 रॉकेट के जरिए नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जुलाई में अंतरिक्ष एजेंसी भारी-भरकम एलवीएम-3 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिका स्थित एएसटी स्पेसमोबाइल इंक के ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करेगी।

सिंह ने कहा कि मई में निर्धारित ग्रुप कैप्टन शुक्ला का मिशन भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर है।

भारतीय वायु सेना के पायलट ग्रुप कैप्टन शुक्ला को इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत चुना गया था और वह गगनयान मिशन के शीर्ष दावेदारों में से एक हैं।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि एक्सिओम-4 मिशन पर उनकी यात्रा से अंतरिक्ष उड़ान संचालन, प्रक्षेपण प्रोटोकॉल, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुकूलन और आपातकालीन तैयारियों में महत्वपूर्ण व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होने की उम्मीद है, जो भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है।

पंजाब में आतंकवादी घटनाओं का भगोड़ा आरोपी हरप्रीत अमेरिका में गिरफ्तार

वाशिंगटन/एजेन्सी। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने पंजाब में कई आतंकवादी घटनाओं में नामजद भगोड़े अभियुक्त हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने की घोषणा की है। हरप्रीत का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से संबंध बताया जाता है। एफबीआई ने सोशल मीडिया पर हरप्रीत के पकड़े जाने की जानकारी दी। एफबीआई ने कहा, भारत के पंजाब में कई आतंकवादी घटनाओं के लिये जिम्मेदार हरप्रीत सिंह को एफबीआई और ईआरओ ने सैक्रामेंटो में पकड़ा है। दो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से संबद्ध हरप्रीत अमेरिका में अवैध तरीके से घुसा था और गिरफ्तारी से बचने के लिये बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहा था। एफबीआई ने कहा, नई दिल्ली स्थित एफबीआई के विधि कार्यालय के प्रतिनिधि ने सैक्रामेंटो के अधिकारियों को सूचित किया था कि हरप्रीत भारत के पंजाब में आतंकवादी वारदात के कई मामलों में वांछित है। ऐसी आशंका है कि हरप्रीत पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) और खालिस्तानी आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से संबंध रखता है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिये पता न चल सकने वाले बर्नर फोन और कूट भाषा वाली अप्लीकेशन का इस्तेमाल करता था।

भारत समावेशी न्याय संगत और सतत कृषि के लिए प्रतिबद्ध : शिवराज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ब्राजीलिया/नई दिल्ली/एजेन्सी। भारत ने समावेशी, न्यायसंगत और सतत कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता तथा संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों से लड़ने में नीतिगत सहायता की आवश्यकता है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ब्राजील के ब्राजीलिया में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में कहा कि भारत समावेशी, न्यायसंगत और सतत कृषि के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण को वैश्विक कृषि रणनीति के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और स्पष्ट किया कि कृषि भारत के लिए केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए आजीविका, भोजन और गरिमा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि जब तक छोटे किसानों को संरक्षित और सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

■ जब तक छोटे किसानों को संरक्षित और सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस पर बल दिया कि दुनिया के 51 करोड छोटे किसान वैश्विक खाद्य प्रणाली की रीढ़ हैं और जलवायु परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता तथा संसाधनों के संदर्भ में वे सबसे अधिक संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा, हम छोटे किसानों को इन चुनौतियों से लड़ने में अकेला नहीं छोड़ सकते, उन्हें हमारी नीतिगत सहायता की आवश्यकता है। चौहान ने क्लस्टर आधारित खेती, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी मॉडल और प्राकृतिक खेती को छोटे किसानों के सामूहिक सशक्तिकरण और बाजार तक बेहतर पहुंच का प्रभावी माध्यम बताया। बैठक में उन्होंने कृषि व्यापार को न्यायसंगत बनाने, वैश्विक मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने और छोटे किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की शाह ने अपील की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के अगले वर्ष मार्च के अंत तक देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त कराने के संकल्प को दोहराते हुए नक्सलियों से यथाशीघ्र हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की है।

शाह ने शुक्रवार को छत्तीसगढ के बीजापुर जिले में 22 कुख्यात नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा , छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में विभिन्न ऑपरेशन्स में कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 22 कुख्यात नक्सलियों को आधुनिक हथियारों और विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है।

साथ ही, सुकमा की बडेसेट्टी पंचायत में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह पंचायत पूरी तरह नक्सलमुक्त हो गई है।

छिपे हुए नक्सलियों से मेरी अपील है कि मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर यथाशीघ्र हथियार डालें और मुख्यधारा में शामिल हों। 31 मार्च 2026 से पहले हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं।

सूर्यास्त	सूर्योदय
19-04-2025 6:22 बजे	20-04-2025 6:53 बजे

BSE	NSE
78,553.20	23,851.65
(+1,508.91)	(+414.45)

सोना	चांदी
9,312 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	102,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

टैरिफ टेरर

ट्रम्प टोटकाबाज के,
सबसे न्यारे ढंग।
टैरिफ टेरर से पड़ा,
आज रंग में भंग।
भाव स्वर्ण के देख कर,
सारी दुनिया दंग।
लुढ़क रहा सेंसेक्स नित,
बाज़ारों में जंग।।

यमन के तेल बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमलों में 74 लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। यमन के हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को दावा किया कि तेल बंदरगाह को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है जबकि 171 अन्य घायल हैं। यमन की राजधानी सना में विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में रात भर किए गए हमलों से हुई तबाही का उल्लेख किया गया है, जिसमें ईंधन ट्रकों में आग लग गई और रात के समय आसमान में आग के गोले धधक उठे। यह हमला 15 मार्च से जारी अमेरिकी हवाई हमलों की शृंखला में सबसे घातक हमलों में से एक था। हमलों में नागरिकों के हताहत होने के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे यमन बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमलों में नष्ट हुए टैंक और वाहन

दुबई/एपी। सैटेलाइट तस्वीरों में यमन बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमलों में नष्ट हुए टैंक और वाहन देखे जा सकते हैं। शुक्रवार को प्राप्त इन तस्वीरों में लाल सागर में तेल रिसाव भी पाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में यमन के हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले रास ईसा बंदरगाह पर हुए नुकसान को देखा जा सकता है।

यमन के हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को दावा किया कि तेल बंदरगाह को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है, जबकि 171 घायल हैं।

अमेरिकी सेना ने हमले में हताहतों की संख्या के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही किसी क्षति का आकलन पेश किया है।

मोदी ने मस्क से दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

नई दिल्ली/एजेन्सी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिकी उद्योगपति एवं अमेरिकी प्रशासन में प्रशासनिक सुधार एलन मस्क से टेलीफोन पर बात की और प्रौद्योगिकी एवं नवान्वेषण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की। मोदी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा,एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों के बारे में बात की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन में हमारी बैठक के दौरान हमने जिन विषयों को कवर किया था। हमने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

साठ साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधे भाजपा नेता दिलीप घोष

कहा- मां की इच्छा के कारण शादी की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष शुक्रवार को एक निजी समारोह में पार्टी सहयोगी रिंकू मजूमदार के साथ विवाह बंधन में बंध गए। पारंपरिक बंगाली शादी के परिधान में सिर पर टोपी लगाए घोष अपनी पत्नी के साथ रस्मों के बाद प्रेस के सामने आए और लोगों का आशीर्वाद लिया। कोलकाता के पास न्यू टाउन में अपने आवास के बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों से उन्होंने कहा, ''मैं सभी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं। मेरे निजी जीवन का मेरे राजनीतिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।''

साठ वर्षीय घोष ने कहा कि उन्होंने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए शादी करने का फैसला किया। घोष अब तक कुंवारे थे, लेकिन मजूमदार की यह दूसरी शादी है और उन्हें पहले से एक बेटा है।

वैष्णव को अमेरिकी उप राष्ट्रपति की यात्रा से सकारात्मक परिणाम मिलने का भरोसा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मानेसर/भाषा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगले सप्ताह भारत यात्रा से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इस यात्रा से 'सकारात्मक परिणाम' मिलने की उम्मीद जताई।

वैष्णव ने दोनों पक्षों की ओर से व्यावहारिक दृष्टिकोण और निरंतर सहभागिता का हवाला देते हुए कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में उभरा है। वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज के एक कार्यक्रम के दौरान वेंस की भारत यात्रा से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम होंगे, क्योंकि हमने इस मामले को बहुत ही व्यावहारिक और सक्रिय तरीके से लिया है तथा हम इसमें लगातार लगे हुए हैं।

वैष्णव ने कहा, समय के साथ भारत एक बहुत ही विश्वसनीय देश के रूप में उभरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विदेश नीति का संचालन किया है, उससे आज हमारे देश के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, वह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारक होने वाला है।

यह पूछे जाने पर कि क्या चीन के साथ चल रहे तीव्र व्यापार और शुल्क युद्ध को देखते हुए देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डंपिंग होने की कोई आशंका है, मंत्री ने कहा कि हमारा देश किसी भी स्थिति के लिए कमोबेश तैयार है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नोडल प्राधिकारी वाणिज्य मंत्रालय होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा खनिजों पर चीन के निर्यात प्रतिबंधों का भारतीय उपकरण विनिर्माण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, मंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग का मानना है कि वे विकल्प तलाशने में सक्षम होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, अब तक उद्योग जगत के साथ हमारी जो भी चर्चा हुई है, उससे उद्योग जगत को लगता है कि वे इसके विकल्प तलाशने में सफल होंगे, क्योंकि कोविड महामारी के आने के बाद से ही पूरी दुनिया मूल्य शृंखलाओं में विविधता लाने की तैयारी कर रही है। वैष्णव ने कहा, उद्योग के लिए कोविड महामारी से सबसे बड़ी सीख यह थी कि विविध आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए दुनिया उस दिशा में काम कर रही है।

मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर सोमैया का प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने शुक्रवार को मुंबई के मुलुंड क्षेत्र में कुछ मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

उन्होंने कहा कि इनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। यह विरोध प्रदर्शन मुलुंड पुलिस थाना के बाहर आयोजित किया गया। सोमैया ने कहा, ''अदालत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से ऐसे अवैध लाउडस्पीकर को हटाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।'' उन्होंने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने वाले पुलिस थानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।

पूर्व लोकसभा सदस्य ने कहा, ''मैं इस मुद्दे पर लोगों को संवेदनशील बनाने और अवैध लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा कर रहा हूं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि मुलुंड पुलिस थाना के कर्मियों ने इस संबंध में अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और शिवसेना (उबाठा) से जुड़े कुछ नेता उन पर दबाव बनाने और ऐसे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, ''मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।'' स्थानीय भाजपा विधायक मिहित कोटेचा ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

बीएमसी ने 'अनधिकृत' जैन मंदिर को गिराया, समुदाय ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया

मुंबई/भाषा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने विले पार्ले इलाके में कथित तौर पर अनधिकृत जैन मंदिर को गिरा दिया। समुदाय के सदस्यों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया। कांबलीवाड़ी में नेमिनाथ सहकारी आवास सोसाइटी के अंदर स्थित मंदिर (चैतलया) के ट्रस्टी अनिल शाह ने कहा कि इसे 16 अप्रैल को ढहा दिया गया। शाह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह संरचना 1960 के दशक की थी और बीएमसी की अनुमति से इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। उन्होंने दावा किया, एक सरकारी प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि ऐसी संरचनाओं को नियमित किया जा सकता है। आपको केवल बीएमसी को नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और हमने वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।'' शाह ने दावा किया कि मंदिर को ढहाए जाने के दौरान कुछ धार्मिक पुस्तकें और मंदिर का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई एक स्थानीय होटल व्यवसायी के इशारे पर की गई थी। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों ने शनिवार को के-ईस्ट वार्ड कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई है। बीएमसी प्रवक्ता ने निगम का पक्ष जानने के लिए की गई कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया।

2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार नहीं: वित्त मंत्रालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार के 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार करने की खबरों पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''फिलहाल सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।'' जीएसटी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे कुछ खास शुल्कों पर लगाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जनवरी 2020 से ग्राहक से व्यापारी (पीटूएम) के बीच यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर हटा दिया है। मंत्रालय ने कहा, ''चूंकि इस समय यूपीआई लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं लगाया जाता है, इसलिए इन लेनदेन पर कोई जीएसटी लागू नहीं है।''

यूपीआई लेनदेन में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2025 तक 260.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार यूपीआई के जरिये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

जमीन की कीमत में तेज वृद्धि पर पूछताछ होना स्वाभाविक, भाजपा सांसद ने रॉबर्ट वाड्रा मामले में कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भूमि सौदों के मूल्य में 'तेज वृद्धि' के कारण की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा (56) का बयान बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन करीब छह घंटे तक हरियाणा में 2008 के भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में दर्ज किया। बृहस्पतिवार तक उनसे कुल मिलाकर करीब 16 घंटे पूछताछ की गई।

वाड्रा के खिलाफ ताजा जांच हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर-शिकोहपुर (अब सेक्टर 83) में एक भूमि सौदे से जुड़ी है। फरवरी 2008 का यह सौदा स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने किया था। वाड्रा पहले इसके निदेशक थे। कंपनी ने शिकोहपुर में 7.5 करोड़ रुपए की कीमत पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी और फिर इसे 2012 में रियल इस्टेट समूह डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया।

सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने एक कंपनी से सात करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और इसे उसी कंपनी को 58 करोड़ रुपए में वापस बेच दिया। जब एक जमीन सौदे में कम समय में मूल्य में इतनी तेज वृद्धि दिखाई देती है तो यह स्वाभाविक रूप से जांच का विषय होगा।''

यातायात रडार उपकरण सत्यापन के लिए नए नियम एक जुलाई से होंगे लागू : सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में सड़क सुरक्षा और प्रावधानों को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए यातायात रडार उपकरणों के अनिवार्य सत्यापन और मुहर लगाने की आवश्यकता वाले नए नियम एक जुलाई, 2025 से लागू किए जाएंगे।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं, विनिर्माताओं और वाहन प्रमाणन संगठनों सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद नियमों को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने बयान में कहा, ये नियम एक जुलाई, 2025 से लागू होंगे। इससे उद्योगों और प्रवर्तन एजेंसियों को प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। नए नियम विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत आते हैं। ये सड़कों पर वाहनों की गति मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 'माइक्रोवेव डॉपलर रडार उपकरण' पर लागू होंगे।

ये नियम विस्तृत तकनीकी और सुरक्षा जरूरतों को निर्दिष्ट करते हैं, उचित अंशांकन, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्थिर संचालन और छेड़छाड़ के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऐसे उपायों से प्रौद्योगिकी विश्वसनीयता और कानूनी जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। नए ढांचे के अनुसार सभी गति माप उपकरणों को सत्यापन से गुजरना होगा और तैनाती से पहले आधिकारिक सत्यापन और मुहर प्राप्त करनी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य गति और दूरी माप के लिए सटीक आंकड़ों की गारंटी देना है, जो यातायात कानून लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन नियमों के कार्यान्वयन से सभी पक्षों को कई लाभ मिलेंगे। आम नागरिकों के लिए, रडार आधारित गति माप उपकरणों का अनिवार्य सत्यापन और स्टाम्पिंग, गति सीमाओं के सटीक प्रवर्तन को सुनिश्चित करेगा, जिससे अनुचित दंड को रोका जा सकेगा।

धनखड़ से असहमत, अधिकारों की रक्षा करने वाली ''परमाणु मिसाइल'' है न्यायिक स्वतंत्रता: सुरजेवाला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने न्यायपालिका को लेकर उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई टिप्पणी से शुक्रवार को असहमति जताई और कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता सत्ता में बैठे लोगों के मनमाने कार्यों और निर्णयों के खिलाफ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वास्तव में एक ''परमाणु मिसाइल'' है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोकतंत्र में कोई संवैधानिक पद नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च है।

राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने बृहस्पतिवार को न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने और 'सुपर संसद' के रूप में कार्य करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय लोकतांत्रिक ताकतों पर 'परमाणु मिसाइल' नहीं दाग सकता।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 142 को ''न्यायपालिका को चौबीसों घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल'' करार दिया।

सुरजेवाला ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, '' मैं माननीय उपराष्ट्रपति का उनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता, दोनों के लिए बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनके शब्दों से ससम्मान असहमत हूं।'' उन्होंने कहा कि राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक बंधन लगाने वाला उच्चतम न्यायालय का निर्णय सामयिक, सटीक, साहसी हैं और इस धारणा को दुरुस्त करता है कि 'उच्च पदों पर रहने वाले लोग अपनी शक्तियों के उपयोग में किसी भी बंधन या नियंत्रण और संतुलन लगाने से ऊपर हैं।'

राज्यसभा सदस्य ने कहा, ''हमारे लोकतंत्र में भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। कोई भी कार्यालय, चाहे वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल का हो, इतना ऊंचा नहीं है कि वह संवैधानिक औचित्य के दायरे से ऊपर हो।

सुरजेवाला के मुताबिक, ''भारतीय लोकतंत्र निर्वाचित संसद और विधानमंडलों के माध्यम से व्यक्त 'लोगों की इच्छा' के मूल सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सर्वोच्च निकाय संसद और विधानमंडल हैं। यहां तक कि उनके फैसले और कानून बनाने की शक्तियां भी संवैधानिकता की कसौटी पर अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।''

उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति के कदम समीक्षा के अधीन क्यों नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब राज्यपाल भारत सरकार के केवल नामांकित व्यक्ति होते हैं और राष्ट्रपति को संसद और विधानमंडलों द्वारा चुना जाता है?

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ' क्या यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के पारित संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को अनिश्चित काल तक सहमति देने की एकतरफा या अनियंत्रित शक्ति है?

उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपालों के पास ऐसी शक्ति होगी, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा और निर्वाचित संसद तथा विधानमंडल शक्तिहीन और असहाय हो जाएंगे।

इस्पात, एल्युमीनियम पर शुल्क सुरक्षा कारणों से लगाया गया: अमेरिका

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन से कहा है कि इस्पात तथा एल्युमीनियम पर शुल्क लगाने का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया और इसे उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम यानी रक्षोपाय उपाय नहीं माना जाना चाहिए। भारत के 11 अप्रैल को अमेरिका के साथ डब्ल्यूटीओ के सुरक्षा समझौते के तहत परामर्श का अनुरोध करने के बाद अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समक्ष अपना रुख स्पष्ट किया है।

भारत ने कहा था कि अमेरिका द्वारा इन उपायों को सुरक्षा उपाय बताए जाने के बावजूद ये मूलतः उद्योगों के हितों के लिए उठाए गए कदम हैं। इससे अमेरिका इन उपायों को लागू करने के निर्णय के बारे में रक्षोपाय समझौते के प्रावधान के तहत डब्ल्यूटीओ सुरक्षा समिति को सूचित करने में विफल रहा है। अमेरिका ने 17 अप्रैल को डब्ल्यूटीओ को भेजे पत्र में कहा, '' उसने पाया कि रक्षोपाय उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 12.3 के तहत परामर्श के लिए भारत के अनुरोध का आधार यह है कि शुल्क उद्योग के हितों के लिए उठाया कदम है (अमेरिका के) राष्ट्रपति ने धारा 232 के तहत इस्पात तथा एल्युमीनियम पर शुल्क लगाया। इसके तहत राष्ट्रपति ने निर्धारित किया कि शुल्क इस्पात व एल्युमीनियम वस्तुओं के आयात को समायोजित करने के लिए आवश्यक हैं जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने की आशंका है।'' धारा 232 एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है तथा शुल्क को शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 के एक प्रावधान के तहत सुरक्षा अपवाद के तहत रखा जा रहा है।

नेशनल हेराल्ड मामले में 'जनता के पैसे के गबन' को लेकर भाजपा का कांग्रेस कार्यालय के निकट प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नेशनल हेराल्ड मामले में जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस के अकबर रोड कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की।

भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर इकाई के कार्यकर्ता मान सिंह रोड पर एकत्र हुए, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए और भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी का नाम आने पर उनके इस्तीफे की मांग की। सचदेवा ने कहा, मामला 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का कम मूल्यांकन करने से जुड़ा है, जिसे 50 लाख रुपए में मां ने अपने बेटे को सौंप दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में धनशोधन के आरोप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। कांग्रेस ने आरोपपत्र को प्रतिशोध की राजनीति बताया है। सचदेवा ने पूछा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्होंने जमानत के लिए आवेदन क्यों किया। उन्होंने कहा, इसके बजाय उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी और खुद को सही साबित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला साजिश, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला है जिसके लिए कांग्रेस नेता जवाबदेह हैं। सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा चुराए गए सार्वजनिक धन का एक-एक पैसा वसूला जाएगा। उन्होंने पूछा, यह मामला 2012 का है, जब कांग्रेस की सरकार थी। जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो कांग्रेस नेता हैरान क्यों हैं? विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली अध्यक्ष सागर त्यागी और राष्ट्रीय महासचिव रोहित चहल भी शामिल हुए।

सीबीआई ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में छत्तीसगढ़ में पांच स्थानों पर छापेमारी की

रायपुर/भाषा। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में रायपुर और महासमुंद जिलों में पांच स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने रायपुर में तीन और महासमुंद में दो स्थानों पर पांच व्यक्तियों (बिचौलियों/सॉल्वर आदि) के परिसरों पर तलाशी ली। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले से संबंधित मामले की जांच के दौरान इन व्यक्तियों की भूमिका सामने आई। पिछले वर्ष जुलाई में सीबीआई ने 2020-2022 परीक्षा के दौरान सीजीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक और अन्य वरिष्ठ सरकारी पदों के लिए चयन में पक्षपात के आरोप में छत्तीसगढ़ में दर्ज दो मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी ने अब तक मामले में सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, उनके भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, तत्कालीन उप नियंत्रक परीक्षा (सीजीपीएससी) ललित गणवीर, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल व बहू भूमिका शामिल हैं।

गुजरात में अकेले उपचुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 'आप' के साथ नहीं होगा गठबंधन: गोहिल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह दो विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी।

पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी ने उपचुनावों में 'आप' से दूर रहने का फैसला किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने बिना उससे परामर्श किए विसावदर सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि गुजरात में कांग्रेस के इस रुख के बावजूद दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी। गोहिल ने संकेत दिया कि 'आप' ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद विसावदर सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करके गठबंधन धर्म नहीं निभाया। निर्वाचन आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन 'आप' ने पिछले महीने पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को विसावदर सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। गोहिल ने कहा, हमारी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में आगामी उपचुनावों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हर गठबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं। 'आप' ने हमसे सलाह-मशविरा किए बिना ही विसावदर के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन, पार्टी की प्रदेश इकाइयां अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव इसलिए हारी क्योंकि 'आप' ने कुछ सीटों पर उसकी पेशकश स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 'आप' के लिए भरूच और भावनगर सीट छोड़ी थीं। गोहिल ने कहा, इसलिए हमने सर्वसम्मति से आगामी उपचुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। यह भी एक तथ्य है कि गुजरात के मतदाताओं ने कभी किसी तीसरी पार्टी को स्वीकार नहीं किया। आप द्वारा किए गए नुकसान के बावजूद, कांग्रेस अब भी यहां सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लोगों के हित में, कांग्रेस इन सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

आईसीजी जहाज 'विग्रह' ने जाल में फंसे दो लुप्तप्राय कछुओं को छुड़ाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) के जहाज 'विग्रह' के चालक दल ने लुप्तप्राय प्रजाति के ओलिव रिडले के दो कछुओं को बचाया, जो समुद्र में छोड़ दिये गए करीब 600 किलोग्राम के जाल में उलझे हुए थे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

ओलिव रिडले कछुए हर साल फरवरी और मार्च के बीच ओडिशा तट पर लाखों की संख्या में आते हैं।

आईसीजी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''भारतीय तटरक्षक के जहाज विग्रह ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत लुप्तप्राय प्रजाति ओलिव रिडले के दो कछुओं को छुड़ाया, जो लगभग 600 किलोग्राम जाल में उलझे हुए थे। हमारे समुद्री रक्षक समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

आईसीजी ने इस अभियान की एक तस्वीर और एक वीडियो क्लिप भी साझा की है।

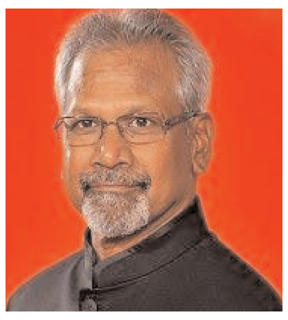

कमल हासन का सिनेमा के प्रति जुनून नहीं बदला : मणिरत्नम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। जाने-माने फिल्म निर्माता मणिरत्नम ने अपनी फिल्म 'ठग लाइफ' के अभिनेता कमल हासन की प्रशंसा करते हुए शुक्रवार को कहा कि सुपरस्टार न सिर्फ एक शानदार अभिनेता हैं बल्कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सिनेमा के प्रति जुनून नहीं बदला है।

हासन और मणिरत्नम 35 साल के अंतराल के बाद इस फिल्म के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। यह तमिल सुपरस्टार की 234वीं फिल्म होगी। दोनों ने इससे पहले 1987 की हिट फिल्म नायकन के लिए काम किया था। मणिरत्नम ने फिल्म के गीत जारी किये जाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ऐसा नहीं है कि वह (हासन) सिर्फ एक शानदार अभिनेता हैं। पूरी दुनिया यह जानती है। सच तो यह है कि उन्हें अभी भी सिनेमा से प्यार है।

पोन्नियिन सेल्वन के निर्देशक मणिरत्नम ने कहा कि हासन जैसी क्षमता वाले अभिनेता का होना उनके लिए वास्तविक लाभ है, क्योंकि अभिनेता फिल्म निर्माता पर से 50 प्रतिशत बोझ हटा देते हैं। उन्होंने कहा, वह बहुत सी चीजों का ख्याल रखते हैं। न केवल खुद का, बल्कि अपने आस-पास के लोगों का, अपने आस-पास के सभी अभिनेताओं का, इसलिए यह सब विश्वसनीय और बहुत वास्तविक लगता है... मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उत्साह बिल्कुल भी नहीं बदला है। फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने तैयार किया है। निर्माताओं ने यहां एक कार्यक्रम में फिल्म का पहला गाना जिंगुचा जारी किया।

स्टालिन ने नीट एवं परिसीमन पर अमित शाह को चुनौती दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवल्लूर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गयी उस आलोचना को लेकर शुक्रवार को उन्हें निशाना बनाया, जिसमें कहा गया है कि राज्य की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार 'भटकाने वाली' रणनीति के तौर पर नीट और परिसीमन जैसे मुद्दों का राग अलाप रही है। स्टालिन ने शाह को चुनौती दी कि वह राज्य की जनता के समक्ष साबित कर दें कि क्या वाकई राज्य सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के मौके पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि तमिलनाडु एवं द्रमुक, नीट समेत अन्य मुद्दों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, चाहे वह नीट हो या त्रि-भाषा नीति, वक्फ संशोधन अधिनियम या परिसीमन- जिससे कुछ राज्यों के प्रभावित होने की संभावना है- केवल हम ही पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि हम ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि तमिलनाडु सभी भारतीय राज्यों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है।

सत्तारूढ़ द्रमुक के अध्यक्ष स्टालिन ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का

रुख किया और राज्यपाल के खिलाफ 'ऐतिहासिक फैसला' मिला, क्योंकि उन्होंने 'कुछ नहीं किया'। उन्होंने कहा कि यह द्रमुक की शक्ति थी और इसे पूरे देश में महसूस किया गया है।

उन्होंने शाह से आगे पूछा, क्या आप कह सकते हैं कि आप नीट से छूट दे सकते हैं, क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि हिंदी नहीं थोपी जाएगी, क्या आप तमिलनाडु को दिए गए (केंद्रीय) फंड की सूची दे सकते हैं और क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि परिसीमन के कारण (संसदीय) प्रतिनिधित्व (सीट) कम नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर हम जो कर रहे हैं वह ध्यान भटकाने वाला है, तो आपने इन मुद्दों पर तमिलनाडु के लोगों को स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिए।

अमित शाह ने 11 अप्रैल को द्रमुक पर हमला करते हुए उस पर गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए परिसीमन और त्रि-भाषा नीति जैसे मुद्दे उठाने का आरोप लगाया था, और चेतावनी दी थी कि लोग व्यापक भ्रष्टाचार पर सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेतृत्व से जवाब मांगेंगे। शाह द्वारा विपक्षी अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन करने और राजग के 2026 के चुनावों में जीतने का विश्वास जताने पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के अधीन नहीं होगा, हमारा चरित्र बहुत अनूठा है.. छापे और धमकी के जरिये दूसरे राज्यों में पार्टियों को तोड़ने का आपका फॉर्मूला तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। उन्होंने शाह समेत भाजपा के मंत्रियों पर अतीत में तमिलों के बारे में बुरा बोलने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, तमिल भूमि स्वाभिमान और वीरता की धरती है, जिसने कभी वर्चस्व की अनुमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम गुलाम नहीं हैं जो धमकियों के आगे झुक जाएंगे। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, कोई भी शाह हम पर शासन नहीं कर सकता, यह तमिलनाडु है।

तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख सेल्वापेरुन्थगई ने द्रमुक सरकार से जाति सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष सेल्वापेरुन्थगई ने शुक्रवार को यहां कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के पक्ष में है और संबंधित कवायद यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य लाभ सही अनुपात में सही लोगों तक पहुंचें। कांग्रेस द्वारा अपने शासन वाले राज्यों में जाति सर्वेक्षण कराए जाने के बारे में पूछे जाने पर सेल्वापेरुन्थगई ने 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा कि हालांकि केंद्र को जाति जनगणना करानी चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी का रुख यह है कि राज्य सरकारें जाति सर्वेक्षण करा सकती हैं।

कांग्रेस तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। जनगणना संविधान की संघ सूची के अंतर्गत एक विषय है। उन्होंने कहा, हम आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, हम तमिलनाडु सरकार से ऐसा करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि कल्याणकारी योजनाएं और लाभ सही अनुपात में वास्तविक लोगों तक पहुंच सकें। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी का 2006-11 के दौरान अकसर सुना जाने वाला सत्ता में हिस्सेदारी का नारा अब भी जारी रहेगा, उन्होंने कहा, यह एक नीतिगत मामला है। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने के लिए (सहयोगी से) कितनी सीट मांगी जानी चाहिए और पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी मांगनी चाहिए या नहीं, जैसे मामलों पर निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही कर सकती है। हाल ही में, पार्टी के एक पदाधिकारी ने सेल्वापेरुन्थगई को वर्ष 2026 का उपमुख्यमंत्री बताया था और सत्ता में हिस्सेदारी की वकालत की थी। तमिलनाडु में अगले साल

विधानसभा चुनाव होना है।

सत्तारूढ़ द्रमुक के साथ उनके अत्यधिक मित्रवत व्यवहार को लेकर उनकी पार्टी के कुछ हलकों में भी आलोचना होने से जुड़े सवाल पर सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि उनकी पार्टी और द्रमुक के बीच विचारधारा से प्रेरित गठबंधन लगातार चुनावी जीत के साथ सफल रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका 'स्ट्राइक रेट' शत- प्रतिशत था। द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टालिन ने 2019 में पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया था। सेल्वापेरुन्थगई ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में क्या द्रमुक नेतृत्व के साथ दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना तथा ईमानदार और सच्ची दोस्ती बनाए रखना सही नहीं है। इसलिए आलोचना पूर्वाग्रह से प्रेरित है।जमीनी स्तर पर कांग्रेस की मजबूती पर उन्होंने कहा कि पार्टी की ग्राम समितियों में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई डेटाबेस नहीं था, लेकिन अब यह बनाया जा रहा है और पदाधिकारियों को क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र दिए जा रहे हैं तथा ग्राम समितियों के पदाधिकारियों का 53 प्रतिशत डेटाबेस तैयार है। अन्नाद्रमुक-भाजपा के बीच संबंधों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि वह भाजपा के साथ कभी कोई संबंध नहीं रखेगी और उन्हें आश्चर्य है कि अब गठबंधन कैसे बन गया। उन्होंने पूछा, क्या यह मजबूरी है या धमकी?

द्रमुक ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर धनखड़ की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश को लेकर न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से की गई टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की।

द्रमुक ने यह भी कहा कि न्यायालय की व्यवस्था को लेकर उपराष्ट्रपति की आलोचना ''अनैतिक'' है। पार्टी के उप महासचिव और राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा, ''संविधान के अनुसार शक्तियों के बंटवारे के तहत, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पास अलग-अलग शक्तियां हैं।'' उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''जब तीनों अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं तो किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर हाल ही में उच्चतम न्यायालय के फैसले में अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए निस्संदेह यह स्थापित किया गया है कि संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाम पर कोई भी विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रख सकता।''

वरिष्ठ नेता ने कहा, ''उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर टिप्पणियां अनैतिक हैं। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि भारत में ''कानून का शासन'' कायम है।''

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने और 'सुपर संसद' के रूप में कार्य करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय लोकतांत्रिक ताकतों पर 'परमाणु मिसाइल' नहीं दाग सकता।

धनखड़ ने न्यायपालिका के प्रति यह कड़ी टिप्पणी राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए की। कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय की थी। उन्होंने कहा था, '' हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका के कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।''

उपराष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 142 को ''न्यायपालिका को चौबीसों घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल'' करार दिया।

कोच्चि में भोजन विषाक्तता के कारण 12 प्रवासी श्रमिक अस्पताल में भर्ती

कोच्चि/भाषा। कोच्चि में भोजन विषाक्तता के एक मामले में 12 प्रवासी श्रमिकों को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। श्रमिकों को अपराह्न में दस्त और उल्टी जैसी शिकायत होने लगी जिसके बाद उन्हें त्रिपुणितुरा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, बाद में उन्हें कलमश्शेरी में एर्नाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेजा गया और रात करीब साढ़े आठ बजे उन्हें आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि घर पर बने भोजन का सेवन करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. गणेश मोहन ने बताया कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है।

कर्नाटक में सीईटी परीक्षा केंद्र पर छात्रों से जनेऊ उतारने के लिए कहे जाने पर विवाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिलों के केंद्रों पर सीईटी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले कुछ छात्रों को कथित तौर पर जनेऊ (ब्राह्मणों द्वारा पहना जाने वाला धागा) उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों का चयन करने हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाती है।

अधिकारियों के अनुसार, बीदर में एक छात्र को बृहस्पतिवार सुबह गणित का पेपर दिए बिना ही घर लौटना पड़ा, क्योंकि साईं स्फूर्ति कॉलेज में परीक्षा केंद्र की स्क्रीनिंग कमेटी ने कथित तौर पर उससे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले जनेऊ उतारने को कहा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लड़के ने स्टाफ (तलाशी दल में शामिल पुलिस कर्मियों) से गुहार लगाई कि उसे केंद्र में जाने दिया जाए, क्योंकि जनेऊ पहनने से उसके किसी कदाचार में शामिल होने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि, स्टाफ ने उसे यह कहते हुए प्रवेश नहीं दिया कि इससे वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। उससे कहा गया कि वह जनेऊ हटाकर परीक्षा केंद्र में जाए। लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और गणित का पेपर दिए बिना ही केंद्र से चला गया।

हालांकि, बाद में (बृहस्पतिवार) दोपहर को लड़के को जनेऊ पहनकर जीव विज्ञान की परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इसी छात्र ने एक दिन पहले बिना किसी समस्या के जनेऊ पहनकर भौतिकी और रसायन विज्ञान की परीक्षा भी दी थी। बीदर में आज पत्रकारों से बात करते हुए परीक्षा देने से चूके छात्र ने कहा, कॉलेज प्रबंधन और पुलिस जैसे दिखने वाले तीन लोगों ने मुझसे जनेऊ उतारकर आने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बाद ही मुझे पेपर देने की अनुमति दी जाएगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या केवल उन्हें ही या अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा, केवल मुझे ही ऐसा करने के लिए कहा गया था, अन्य लोगों को जांच के बाद सामान्य रूप से अनुमति दी गई थी। मैंने उनसे कहा कि ब्राह्मण समुदाय में जनेऊ हटाने की अनुमति नहीं है और मुझे भौतिकी व रसायन विज्ञान के पेपर के लिए अनुमति दी गई थी, गणित के पेपर के लिए ऐसा प्रतिबंध क्यों था। उन्होंने कहा, अन्य पेपरों के लिए उचित जांच नहीं की गई थी और वे अब ऐसा कर रहे थे। मैं 45 मिनट तक अनुरोध करता रहा। बीदर की उपायुक्त शिल्पा शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उक्त केंद्र के मुख्य परीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस तरह के व्यवहार के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीदर के पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वासन दिया है कि वह तलाशी टीम को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

शिवमोगा पुलिस के अनुसार, बुधवार को आदिचुंचनगिरी पीयू कॉलेज परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कर्मचारियों ने तीन छात्रों से कथित तौर पर जनेऊ उतारने को कहा। आरोपों के अनुसार, एक छात्र ने जनेऊ उतारने से इनकार कर दिया और उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई, जबकि अन्य दो ने परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले जनेऊ उतार दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें अभिभावकों की ओर से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन जांच के अनुसार, जब हमने कॉलेज अधिकारियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए केवल भवन दिया गया है और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने या अन्य व्यवस्थाओं में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जबकि परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने किसी भी छात्र से कमीज या जनेऊ उतारने के लिए नहीं कहा। नियमानुसार, उन्होंने केवल छात्रों से कशी धारा (कलाई के चारों ओर पहना जाने वाला धागा) उतारने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, इन आरोपों की पुष्टि की जानी चाहिए और इसके लिए विस्तृत जांच की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री एम. सी. सुधाकर ने कहा कि अगर ऐसी घटना हुई है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है तो यह निंदनीय है और ऐसी बातें स्वीकार नहीं की जा सकतीं। उन्होंने कहा, मैं एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाऊंगा, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार क्या कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वह भी ऐसी घटना के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हैं।

केरल सरकार ने अभिनेत्री विंसी अलोशियस के आरोपों पर कार्रवाई का वादा किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों को लेकर मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री विंसी अलोशियस के हालिया आरोपों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अलोशियस ने आरोप लगाया था कि उनके साथी कलाकार अभिनेता शाइन टॉम चाको ने एक फिल्म के सेट पर मादक पदार्थों का सेवन किया और उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। राज्य के आबकारी मंत्री एम बी राजेश ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनका विभाग अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मामले की जांच करेगा, भले ही अलोशियस ने अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराई हो।

मंत्री ने यह भी कहा कि फिल्म उद्योग सहित किसी भी क्षेत्र में मादक पदार्थों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजेश ने कहा, जहां तक मादक पदार्थों के सेवन की बात है, वहां किसी भी जगह को छूट नहीं दी जाएगी और न ही विशेष महत्व दिया जाएगा। जहां भी हमें मादक पदार्थों के सेवन की जानकारी मिलेगी, उसकी जांच की जाएगी। अगर हमें फिल्म सेट पर मादक पदार्थ के सेवन की जानकारी मिलती है तो इसकी जांच की जाएगी। फिल्म का सेट कोई पवित्र स्थान नहीं हैं। इसी तरह का रुख अपनाते हुए राज्य के मत्स्य पालन, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने कहा कि अभिनेत्री के आरोप गंभीर हैं। चेरियन ने कहा कि फिल्म उद्योग में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ बिना किसी अपवाद के कार्रवाई की जाएगी।

चेरियन ने एक बयान में कहा कि अलोशियस के आरोपों की जांच की जाएगी। चेरियन ने कहा कि मलयालम फिल्म उद्योग राष्ट्र के लिए एक आदर्श है और इसकी छवि को धूमिल करने वाला कोई भी व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे

पहले, मलयालम फिल्म अभिनेत्री विंसी अलोशियस ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि वह सह-कलाकार द्वारा फिल्म के सेट पर मादक पदार्थ लेने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराएंगी। हालांकि, अलोशियस ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ के लिए संपर्क करती है तो वह अपना अनुभव साझा करेंगी और जांच में पूरा सहयोग देंगी।

उन्होंने बताया कि उन्होंने इस संबंध में शिकायत केरल फिल्म चैंबर और एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (एएमएमए) को दी है और वे इस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। अभिनेत्री ने कहा कि यह घटना एक मलयालम फिल्म के सेट पर हुई थी, जब एक अभिनेता ने नशे की हालत में उनके और एक अन्य महिला सहकर्मी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया था। अलोशियस ने कहा, उस अभिनेता ने अश्लील टिप्पणियां कीं और अस्वीकार्य व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह बात फिल्म के निर्देशक को बताई, जिन्होंने संबंधित अभिनेता को चेतावनी दी कि वह ऐसा व्यवहार दोबारा न करें।

उन्होंने कहा, मैंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिल्म बीच में रुक जाए। अलोशियस ने साफ किया कि उनकी शिकायत फिल्म या उसकी टीम से नहीं है, बल्कि उस अभिनेता से है।

उन्होंने कहा, सेट पर सभी लोग फिल्म पूरी करने का कठिन प्रयास कर रहे थे, इसलिए मैंने औपचारिक शिकायत नहीं की। अभिनेता शाइन टॉम चाको पर सेट पर मादक पदार्थ के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और उन्होंने इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

मंत्रिमंडल में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने शुक्रवार को दावा किया कि बृहस्पतिवार शाम को मंत्रिमंडल की हुई विशेष बैठक में सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस सर्वेक्षण रिर्पोट को 'जाति जनगणना' के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चर्चा के दौरान मंत्रियों के बीच कोई तीखी बहस नहीं हुई, जैसा कि मीडिया के एक वर्ग द्वारा खबर दी गई है।

सिद्दरामय्या ने कहा, कल इस (जाति जनगणना रिपोर्ट) पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई जो अधूरी रही और चर्चा दूसरे दिन के लिए टाल दी गई। इस विषय पर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। किसी ने इसका विरोध

नहीं किया है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मीडिया में आई यह खबरें झूठी हैं कि कुछ मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई थी। उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने भी मंत्रिमंडल की बैठक में किसी भी तरह की नोक-झोंक से इनकार किया है। कुमार ने यहां अलग से संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हमने विचार साझा किए, बस इतना ही। ऊंची आवाज में बोलना या दलील देने जैसा कुछ नहीं हुआ। सुझाव दिए गए। इसके अलावा कुछ भी तय नहीं हुआ। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बैठक के बाद बृहस्पतिवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त मापदंडों पर चर्चा की तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अधिक जानकारी और तकनीकी ब्योरा मांगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल दो मई को एक बार फिर सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करेगा और उस पर निर्णय लेगा।

सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दर्ज कीं तथा कई क्षेत्रों से व्यक्त की गई चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि यह अवैज्ञानिक और पुरानी है तथा इसमें कम गणना की गई है। उन्होंने बताया कि इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने सभी मंत्रियों से लिखित या मौखिक रूप से अपनी राय देने को कहा। सूत्रों ने बताया कि ऐसी खबरें थीं कि सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने नाराजगी भरे लहजे में बात की और इस पर अपनी आपत्ति जताई, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद अन्य मंत्रियों ने इसकी पुष्टि नहीं की।

राहुल ने सिद्दरामय्या से कर्नाटक में 'रोहित वेमुला अधिनियम' लागू करने के लिए कहा

नयी दिल्ली/बेंगलूरु। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में 'रोहित वेमुला अधिनियम' लागू किया जाए ताकि वंचित वर्गों के किसी छात्र को जातिवाद का वो दंश नहीं झेलना पड़े जिसे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर, रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने झेला है। कांग्रेस ने वर्ष 2023 के अपने रायपुर महाधिवेशन में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों का सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'रोहित वेमुला अधिनियम' नामक एक विशेष कानून पारित करेगी।

हैदराबाद विश्विद्यालय के छात्र रहे रोहित वेमुला ने जनवरी, 2016 में कथित जातिगत भेदभाव के

कारण आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिद्दरामय्या को लिखा पत्र शुक्रवार को 'एक्स' पर साझा किया। पत्र 16 अप्रैल की तारीख है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा, हाल ही में संसद में मेरी मुलाक़ात दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बाबासाहेब आंबेडकर ने दिखाया था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वंचित भी सशक्त बन कर जातिभेद को तोड़ सकते हैं। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दशकों बाद भी लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि इसी भेदभाव ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार छात्र-छात्राओं की जान ले ली। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी भयावह घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। उन्होंने कहा कि अब इस अन्याय पर पूरी तरह से रोक लगाने का वक्त है। उन्होंने कहा, मैंने सिद्दरामय्या जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लागू किया जाए। भारत के किसी भी बच्चे को जातिवाद का वो दंश न झेलना पड़े, जो बाबासाहेब आंबेडकर, रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने झेला है।

अश्लीलता के आरोपियों को बचा रही है पुलिस : दिलावर

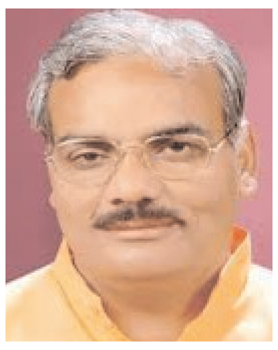

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार तहसील में चर्चित अध्यापक अध्यापिका के अश्लीलता के मामले में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थानीय पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। दिलावर ने शुक्रवार को यहां अपने विभागों की खुली जन सुनवाई के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में उनके अधिकार में जो भी हो सकता था, तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही विभाग द्वारा गंगरार थाने में सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने का मामला भी दर्ज करवाया था।

उन्होंने कहा कि दोनों की तीन महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे पुलिस की ढिलाई है। गृह विभाग उनके पास नहीं होने से वह कुछ नहीं कर सकते। दिलावर ने कहा कि पुलिस मामले की जांच में समय लगने की बात कह रही है। उन्होंने शिक्षा विभाग में वर्षों से जमे अधिकारियों को समायोजन प्रक्रिया में हटाने की बात भी कही जबकि जिले के रावतभाटा के नासेरा की ढाणी में 20 वर्षों से छप्पर में चल रहे प्राथमिक विद्यालय को वन विभाग द्वारा भूमि आवंटित नहीं होने के सवाल पर दिलावर ने कहा कि अगर कोई अपनी व्यक्तिगत भूमि देना चाहे तो हम लेने को तैयार हैं। उन्होंने पंचायत राज के गांवों में सफाई को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि हम राजस्थान के गांवों को सफाई में आदर्श गांव बनाना चाहते हैं।

पेड़ से आम तोड़ने पर बालक की बेरहमी से पिटाई

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में पेड़ से कच्चे आम तोड़ने पर एक बालक की अध्यापक द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बालक के पिता चैन सिंह मीणा ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए शुक्रवार को बताया कि उनका बेटा आवासीय कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेल के दौरान पास ही लगे आम के पेड़ से बच्चों ने कुछ कच्चे आम तोड़ लिए, जिससे नाराज होकर पास में ही रहने वाले अध्यापक ने उनके बेटे को पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर बांध कर बेरहमी से पीटा। थाना अधिकारी गणेश राम ने बताया कि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे का मेडिकल कराया, जिसमें मामूली चोटें पाई गई हैं। अध्यापक के घर पुलिस भेजी गई थी, लेकिन आरोपी मौके पर नहीं मिला।

एक राष्ट्र, एक चुनाव अभियान के डिजिटल संस्करण का विशेष क्यूआर कोड जारी : राठौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अभियान के डिजिटल संस्करण का एक विशेष क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसे स्कैन करके आम नागरिक अपने समर्थन को डिजिटल रूप से दर्ज करा सकते हैं। राठौड़ ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि यह पहल जनभागीदारी को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' केवल एक राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त करने और शासन व्यवस्था को स्थिरता देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने इस विचार का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बार-बार होने वाले चुनावों से न केवल आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादी होती है, बल्कि बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण जनकल्याणकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं।

सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक तंत्र चुनावों में व्यस्त हो जाता है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं और जनता को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1971 के बाद जब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे, तब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता बाधित हुई है। अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को गिराया गया, जिससे संघीय ढांचे को क्षति पहुंची है। चुनावों की बारंबारता पर चिंता जताते हुए राठौड़ ने कहा कि देश में कुछ महीनों के अंतराल में कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान विकास कार्यों से हटकर केवल चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित हो जाता है।

पुलिस, प्रशासन, शिक्षण संस्थान, यहां तक कि आम नागरिकों की दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो सरकारें पूरे पांच वर्षों तक स्थिरता के साथ कार्य कर पाएंगी। इससे नीति निर्माण में सुसंगतता आएगी, विकास योजनाओं की गति बढ़ेगी और संसाधनों की व्यापक बचत होगी। यह बचाए गए संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी संरचना में लगाए जा सकते हैं। राठौड़ ने कहा कि यह सुधार केवल सरकार या किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सामूहिक दायित्व है। जब तक जनता का समर्थन और सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा कोई भी सुधार जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता।

उन्होंने नागरिकों, मीडिया, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे इस पहल के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, जनसमर्थन जुटाएं और इसे सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

खाटू श्याम के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की कार की कंटेनर से टक्कर, दो की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

टोंक। जिले के दतवास थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार दौसा-कोथून हाइवे पर हिंगोनिया मोड़ के पास एक कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को निवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। कार में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के कंदोला गांव के रहने वाले हैं। वे खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए राजस्थान के सीकर जा रहे थे। तभी हिंगोनिया मोड़ के पास सामने से आ रहे एक कंटेनर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी।

दुर्घटना के बाद कार और कंटेनर दोनों पलट गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को निवाई अस्पताल पहुंचाया।

दतवास थाना प्रभारी कालू राम वर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान लक्ष्मी (60) और भगवान सिंह (32) निवासी कंदोला, हापुड़, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं, इसी गांव के वर्षा (19), खुशी (22), विकास (22), राजू (28) और कार चालक घायल हुए हैं। हादसे में घायल विकास ने बताया कि उन्होंने कुछ मिनट पहले ही कार चालक से चाय पीने के लिए कहीं रुकने को कहा था। चालक ने भी हामी भरी, लेकिन चाय की दुकान तक पहुंचने से पहले ही सामने से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी।

भाभी से पड़ोसी के रिश्ते पर ऐतराज जताने पर युवक की हत्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। राजस्थान के कोटा में एक युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया युवक ने अपनी भाभी के पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक के साथ रिश्ते पर ऐतराज जताया था। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय युवक भंवरलाल भील उर्फ भोला का खून से सना शव बृहस्पतिवार को कोटा के डोलिया गांव में एक सुनसान जगह से बरामद किया गया। भोला अपनी भाभी के साथ रहता था जिसका पति फिलहाल जेल में है। रानपुर थाने के क्षेत्राधिकारी रामविलास ने बताया कि महिला के अपने पड़ोस में रहने वाले हेमराज भील के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध थे। हेमराज पर ही अपने साथी बबलू भील की मदद से भंवरलाल की हत्या करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि भंवरलाल को कुछ सप्ताह पहले ही इस संबंध की भनक लगी और उसने दोनों से इसे खत्म करने को कहा। भंवरलाल ने बृहस्पतिवार को हेमराज को देखा और उसे अपनी भाभी से फिर से दूर रहने को कहा। इस पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और हेमराज ने बबलू की मदद से भंवरलाल को पत्थरों और डंडों से कथित तौर पर पीटा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके बाद वे दोनों मौके से भाग गए और बाद में भंवरलाल का शव बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि भंवरलाल के चाचा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हेमराज और बबलू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना लागू

जयपुर।। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 (उच जडढ) लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से ऋणी सदस्यों को पुन मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। दक ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे। अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि ऋणी द्वारा जमा कराये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज और दण्डनीय ब्याज में 100 प्रतिशत राहत दी जाएगी। योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जोधपुरवासियों को मिलेगी नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात : गजेन्द्र सिंह शेखावत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन नई टर्मिनल बिल्डिंग का अवलोकन किया। शेखावत ने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि एयरपोर्ट विस्तार को लेकर जोधपुरवासियों का तीन दशक का सपना पूरा होने जा रहा है। दीपावली पर नए टर्मिनल की सौगात जोधपुरवासियों को मिलेगी और जोधपुर देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ जायेगा। निर्माणाधीन नई टर्मिनल बिल्डिंग में मीडिया से रू-ब-रू होते हुए शेखावत ने कहा कि जोधपुर मरुस्थल का गेट-वे है, उस दृष्टिकोण से भी जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार की अनेक वर्षों से प्रतीक्षा थी। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार में दो तरह की बाधाएं थीं। एक एयरपोर्ट पर भूमि की कमी थी, क्योंकि इसका अधिकांश भाग इंडियन एयरफोर्स के पास है।

दूसरा जोधपुर एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं थी। इसके कारण नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती। 10 साल के लगातार प्रयासों के बाद ये बाधाएं दूर हुई हैं। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाने का काम किया है। शेखावत ने कहा कि जोधपुर राजस्थान का जयपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है। आने वाले समय में जब कभी आवश्यकता होगी, एक महीने के शॉर्ट नोटिस पर जोधपुर एयरपोर्ट को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में कन्वर्ट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार का लाभ जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट, स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल, स्टोन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आदि को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस टर्मिनल के निर्माण से क्षेत्रीय विकास को नया आयाम मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व रक्षामंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए शेखावत ने कहा प्रधानमंत्री के निर्देश पर जब मैं पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के पास इस विषय को लेकर के गया था, तब उन्होंने तत्काल समस्या का समाधान कराया। उनके प्रयासों से राज्य सरकार, नगर निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरफोर्स के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। एयरपोर्ट के लिए आवश्यक 37 एकड़ जमीन मिली। पुराने एयरपोर्ट पर स्थानाभाव में लंबे समय एयरक्राफ्ट को रनवे पर खड़े रहना पड़ता है।

पर्रिकरजी ने इस दर्द को समझते हुए लैंड एक्सचेंज की टेक्निकल फॉर्मेलिटी से पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना काम शुरू करने की अनुमति दिलाई। शेखावत ने तत्कालीन सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू का भी आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से जोधपुर में ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम की सुविधा मिली। उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल की डिजाइन जो जोधपुर की पहचान छीतर पत्थर से तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी भव्यता और स्थानीयता दोनों बरकरार रहेगी।

उन्होंने बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट पर 480 करोड़ रुपए का निर्माण हो रहा है। मल्टीलेवल पार्किंग, जो अभी उत्तर भारत में केवल मुंबई और दिल्ली में है, यहां भी बन रही है। अभी जोधपुर एयरपोर्ट में मात्र 200 पैसेंजर की क्षमता है, जो अब 2000 पैसेंजर की होने वाली है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग अभी 3900 स्क्वायर मीटर की है, जो छह गुना बढ़कर 24 हजार स्क्वायर मीटर होने जा रही है। इंजीनियर्स के मुताबिक नई बिल्डिंग में 20 साल के लिए प्रोविजन किया गया लेकिन जिस तरह से देश में विस्तार हो रहा है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, विश्वास है कि 10 साल तक यह बिल्डिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगी। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एविएशन सेक्टर में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है।

एक भी रोगी के जीवन को नहीं हो खतरा : गायत्री राठौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान भीषण गर्मी एवं हीटवेव की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। इसे देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव को लेकर पुख्ता प्रबंधन सुनिश्चित हो। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। जांच, दवा, उपचार आदि के अभाव में किसी भी रोगी के जीवन को खतरा नहीं होना चाहिए। श्रीमती राठौड़ शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में भीषण गर्मी एवं हीटवेव के दौरान चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक तैयारियों, बजट घोषणाओं एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने राजस्थान में भीषण गर्मी एवं हीटवेव का अत्यधिक प्रभाव रहने की आशंका व्यक्त की है। इसे देखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अस्पतालों में हीटवेव एवं मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप हर चिकित्सा संस्थान में दवाओं की उपलब्धता हो। जरूरत होने पर स्थानीय स्तर पर भी दवाओं की खरीद की जाए, लेकिन दवाओं की कमी नहीं रहे। राज्य स्तर से भी दवाओं की मांग, आपूर्ति एवं वितरण की नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स सहित अन्य चिकित्सा उपकरणों के नियमित मेंटीनेंस पर विशेष जोर दिया।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि हर चिकित्सा संस्थान में पानी, छाया, एसी, कूलर, पंखों आदि की समुचित उपलब्धता एवं क्रियाशीलता को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। अगर किसी भी चिकित्सा संस्थान में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो संबंधित संस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी एसी, कूलर, पंखे या हीटवेव के प्रबंधन हेतु अन्य जरूरी संसाधनों की कमी है तो तात्कालिक आवश्यकतानुसार आरएमआरएस फण्ड से खरीद की जाए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों को हीटवेव प्रबंधन को लेकर दैनिक रिपोर्टिंग करनी होगी। यह रिपोर्टिंग आरक्षित बैड की संख्या, एसी, कूलर, पंखों की क्रियाशीलता, पेयजल की उपलब्धता, एम्बुलेंस, ऑपरेशन थियेटर एवं उपकरणों की क्रियाशीलता, जांच एवं दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं के आधार पर की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को भी हीटवेव प्रबंधन की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं समय-समय पर फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने गर्मी के दौरान खाद्य सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि प्रदेशभर में अभियान चलाकर नियमित निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित की जाए। आमजन को भी खाद्य सामग्री की खरीद एवं उपयोग में मानकों का ध्यान रखने हेतु जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं संतुलित खान-पान से मौसमी बीमारियों से बचाव में बड़ी मदद मिलती है।

प्रमुख शासन सचिव ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए इनका समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा किया जाए, ताकि आमजन को इनका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने एम्बुलेंस के सुचारु संचालन, अस्पतालों में समुचित स्टाफ की उपलब्धता, स्टाफ की कमी होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने, नियंत्रण कक्षों का चौबीस घंटे संचालन करने, आमजन को व्यापक स्तर पर जागरूक करने सहित अन्य दिशा-निर्देश भी दिए।

खान विभाग ने बनाया राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति का रोड़मेप, क्रियान्वयन की कार्ययोजना की जारी : टी. रविकान्त

जयपुर,। राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति का रोड़ मैप बनाकर क्रियान्वयन की कार्ययोजना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने कहा कि प्रबंधकीय दक्षता और ऐप्रोसिव रणनीति बनाते हुए राजस्व लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9228 करोड़ 21 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित कर सर्वाधिक 23.69 प्रतिशत विकासदर के साथ राज्य के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में खान विभाग आगे रहा है। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त शुक्रवार को खनिज भवन में निदेशक माइंस दीपक तंवर और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दे दिए कि खान विभाग राजस्व अर्जन करने वाला प्रमुख विभाग है और ऐसे में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खान विभाग की समीक्षा बैठकों के दौरान, वैध खनन को प्रोत्साहन और राजस्व छीजत को रोकने के निर्देश देते रहे हैं। इसके लिए विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राजस्व प्राप्ति की रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए माइनर और मिनरल ब्लॉक व प्लॉट तैयार कर उनकी समयबद्ध नीलामी के साथ ही न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में स्टे वाले प्रकरणों में प्राथमिकता से स्टे निरस्त कराकर और अन्य प्रकरणों में राशि की वसूली, नीलाम ब्लॉकों व प्लॉटों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने, खनन पट्टों आदि की बकाया किस्तों की वसूली, अवैध खनन या अन्य कारणों से लगाई गई शास्तियों की वसूली के कारगर प्रयास, आरसीसी ईआरसीसी के नोबिड ठेकों की कार्ययोजना बनाकर नीलामी, माइनिंग कंपनियों के अधिशुल्क का निर्धारण और वसूली, जब्त खनिजों की नीलामी और अवैध खनन गतिविधियों की शास्ति राशि की वसूली का रोड मैप बनाते हुए राजस्व संग्रहण के स्पष्ट निर्देश फील्ड अधिकारियों को दे दिए हैं। विभाग द्वारा कार्यालयवार राजस्व संग्रहण के मासिक लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि स्वयं प्रमुख सचिव खान एवं शासन सचिव स्तर पर भी वीसी के माध्यम से राजस्व संग्रहण की नियतकालीन मोनेटरिंग की जाएगी।

उन्होंने विधानसभा प्रश्नों का समय पर उत्तर भिजवाने, संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का निष्पादन, मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव कार्यालय से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरणों का समय पर निस्तारण और प्रकरणों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

ओडिशा में भारी बारिश, आंधी तूफान, एक व्यक्ति की मौत

भुवनेश्वर/भाषा। तटीय ओडिशा में शुक्रवार सुबह भारी बारिश के साथ आये आंधी तूफान में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में पूर्वाह्न 10 से 11.30 बजे के बीच 26.2 मिलीमीटर बारिश हुई और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर और कटक के कई निचले इलाकों में जलभराव की सूचना है। उन्होंने बताया कि कटक के बांकी इलाके में 100 से अधिक पेड़ उखड़ गए, जिससे भुवनेश्वर जाने वाली सड़क अवरुद्ध हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि भुवनेश्वर के पोखरीपुट, ओल्ड टाउन, चिंतामणिश्वर, चंद्रशेखरपुर, गजपति नगर, बेहरा ढाबा और बालाकाटी रोड पर भी पेड़ उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के पंद्रह दल सड़कों को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं के कारण अन्य जिलों में भी पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई।

उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग के कर्मचारी सेवाएं बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। पुरी जिले के सत्यबाड़ी खंड में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे एक अधेड़ किसान की मौत हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार सुबह 8.30 बजे तक मयूरभंज, बालासोर और भद्रक में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने के लिए तैयार रहने के वास्ते 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि आंधी-तूफान की स्थिति 20 अप्रैल तक जारी रहने की आशंका है, जिसके बाद तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।

लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते: सिब्बल

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह ''असंवैधानिक'' है और राज्यसभा के किसी सभापति को कभी भी इस तरह का ''राजनीतिक बयान'' देते नहीं देखा गया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वे ''पार्टी प्रवक्ता'' नहीं हो सकते। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''हर कोई जानता है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीच में होती है। वह सदन के अध्यक्ष होते हैं, किसी एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं। वे मतदान भी नहीं करते हैं, वे केवल तभी मतदान करते हैं जब पक्ष एवं विपक्ष को बराबर मत मिलते हैं। उच्च सदन के साथ भी यही बात है। आप विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच समान दूरी पर हैं।'' सिब्बल का कहना था, ''आप जो कुछ भी कहते हैं वह समान दूरी बनाए रखने वाली होनी चाहिए। कोई भी अध्यक्ष/सभापति किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता कि वह (धनखड़) हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप में कोई भी अध्यक्ष/सभापति किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। अगर ऐसा लगता है तो आसन की गरिमा कम हो जाती है।''

घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामला : ईडी ने नोएडा की रियल्टी कंपनी के प्रवर्तक को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली/भाषा। घर खरीदारों का करीब 107 करोड़ रुपए गबन करने से जुड़े धनशोधन के मामले में नोएडा से संचालित एक रियल एस्टेट कंपनी के मुख्य प्रवर्तक (प्रमोटर) को धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि उन्नति समूह के अनिल मिठास को 16 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। उसने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 24 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। धन शोधन का यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 107 करोड़ रुपए की 'धोखाधड़ी और जालसाजी' के आरोप में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने बताया कि उसकी जांच में खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित अरण्य नामक आवासीय परियोजना के लिए उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड और आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा घर खरीदारों से 2012 और 2019 के बीच 522.9 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई थी।

'अगर चिकित्सक के मन में संवेदना नहीं तो वह चिकित्सक कहलाने लायक नहीं'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि एक चिकित्सक की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना होती है और अगर चिकित्सक के मन में संवेदना नहीं है तो वह चिकित्सक कहलाने का अधिकारी है या नहीं, इस पर जरूर विचार होना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)-गोरखपुर में करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 बिस्तरों की सुविधा वाले ''पावर ग्रिड विश्राम सदन'' का शिलान्यास और भूमि पूजन करने के बाद यहां आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के साथ ही उनके अटेंडेंट (तीमारदारों) की पीड़ा को साझा करते हुए योगी ने कहा, ''एक चिकित्सक अपनी संवेदना से गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है। उसका व्यवहार उसी प्रकार होना चाहिए और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ तीन से चार अटेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए भी संवेदना होनी चाहिए।''

योगी ने कहा कि एम्स-गोरखपुर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2016 में किया और 2019 में पहला बैच प्रवेश लिया। वर्ष 2021 में एम्स-गोरखपुर का लोकार्पण मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में रोपा गया था आज वह एक वटवृक्ष बनकर हजारों पीड़ितों को आरोग्यता का लक्ष्य प्राप्त करने का एक नया केंद्र बन गया है।

योगी ने मरीजों के तीमारदारों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ बुनियादी चीजों को देखना होगा, हम अस्पताल की इमारत तो बना लेते हैं, भवन बनाने के बाद मरीज तो भर्ती हो जाता है लेकिन उसका तीमारदार वहां नहीं रह सकता यह अक्सर देखने को मिलता है।

मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी विहिप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कहा है कि वह शनिवार को देशव्यापी प्रदर्शन कर मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगी। विहिप के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देशभर के हर जिला मुख्यालय में संगठन के सदस्य और समर्थक मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के विरोध में धरना देंगे। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ''हम जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करे।''

कुमार ने दावा किया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए), 'तीन तलाक' और वक्फ (संशोधन) अधिनियम जैसे कई मुद्दों पर हिंसक विरोध केवल पश्चिम बंगाल में हुआ, किसी अन्य राज्य में नहीं। उन्होंने कहा, ''यह गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसी हिंसा केवल पश्चिम बंगाल में ही होती है।'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक में कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा ''पूर्व नियोजित'' थी। विहिप प्रमुख ने पूछा, ''यदि यह पूर्व नियोजित थी, तो क्या राज्य की खुफिया एजेंसियों ने उनकी सरकार को कोई पूर्व सूचना दी थी? और यदि नहीं, तो ऐसी विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो हिंसा को रोकने के लिए एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए?'' उन्होंने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में भीड़ द्वारा की गई सांप्रदायिक हिंसा पर प्रतिक्रिया देने में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि ''हिंसा में सीमा पार बांग्लादेश के तत्व शामिल थे''। कुमार ने कहा कि ''ये घटनाएं आतंकवादी कृत्य के बराबर है'' और इसलिए इनकी जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपी जानी चाहिए।

ईपीएफओ में बड़े पैमाने पर डिजिटल बदलाव, मई-जून में नया आईटी मंच शुरू होगा : मांडविया

रांची/भाषा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों के वास्ते सेवाएं व्यापक करने के लिए बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी कर रहा है और इसका संस्करण 3.0 मई या जून तक शुरू किया जाएगा।

मांडविया ने 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ लाभार्थी नए संस्करण 3.0 पर दावों के तेजी से निपटान के कारण एटीएम से राशि निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा, ''ईपीएफओ जल्द ही एक मजबूत आईटी मंच का संस्करण 3.0 लागू करेगा, जिससे स्वतः दावा निपटान, डिजिटल सुधार और एटीएम आधारित धन निकासी सहित निर्बाध और सरलीकृत सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस बदलाव का उद्देश्य ईपीएफओ को सुलभ और कुशल बनाना है।'' मांडविया के अनुसार, नए संस्करण में जटिल और लंबी, आवेदन भरने की प्रक्रिया या दावों और सुधारों के लिए कार्यालय में जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। लाभार्थी ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके अपने ईपीएफओ खातों और अनुरोध को अपडेट करने और अपनी पेंशन पात्रता की निगरानी करने या धन निकालने में सक्षम होंगे।

बंगाल के राज्यपाल हिंसा पीड़ितों से मिलने मालदा पहुंचे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस मुर्शिदाबाद में साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने के कारण अपना घर-बार छोड़कर पलायन करने वाले पीड़ितों से मिलने के लिए शुक्रवार को पड़ोसी मालदा जिला पहुंचे। हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे अपना दौरा टालने का अनुरोध किया था।

बोस ने मालदा के लिए ट्रेन में सवार होने से पहले कोलकाता में संवाददाताओं से कहा, ''मैं (हिंसा प्रभावित) क्षेत्र में जा रहा हूं।'' उन्होंने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, ''मैं पीड़ितों से मिलूंगा, हिंसा प्रभावित क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट की पुष्टि करूंगा, अस्पतालों, पीड़ितों के आवासों और राहत शिविरों का दौरा करूंगा। राज्य पुलिस और केंद्रीय बल साथ मिलकर काम कर रहे हैं तथा स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। दौरे के बाद, मैं अपनी सिफारिशें भेजूंगा।''

मालदा पहुंचने पर बोस ने कहा, ''शिविरों में, मैं पीड़ितों की शिकायतें सुनूंगा, उनकी जरूरतें जानने की कोशिश करूंगा और उनका निवारण करने के लिए सक्रियता से कदम उठाऊंगा।''

राजभवन सूत्रों ने संकेत दिया कि बोस शनिवार को मुर्शिदाबाद का दौरा कर सकते हैं।

मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियान और जंगीपुर इलाकों में, वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ 11 और 12 अप्रैल को हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

वक्फ अधिनियम उस विचार का उल्लंघन करता है जिस पर राष्ट्र का निर्माण होता है: डेरेक ओ ब्रायन

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने शुक्रवार को कहा कि वक्फ अधिनियम-2025 समानता, व्यक्तिगत स्वायत्तता, संघवाद और उस विचार का उल्लंघन करता है जिस पर राष्ट्र का निर्माण हुआ है।

एक ब्लॉग पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुद्दा केवल भूमि या कानून के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अधिकारों को एक व्यक्ति के लिए फिर से लिखा जा सकता है, तो इसे सभी के लिए दोबारा लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा, ''वक्फ संशोधन विधेयक केवल भूमि या कानून के बारे में नहीं है। यह सम्मान के बारे में है।'' ओ ब्रायन ने ब्लॉग का शीर्षक 'क्या मैं पर्याप्त भारतीय हूं' दिया है । इसमें उन्होंने लिखा है कि लाखों भारतीयों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक एवं हाशिए पर पहुंच चुके समुदायों के लिए, यह एक केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है।'' तृकां नेता ने कहा, ''यह एक बोझ है। यह उनके होने पर गहरा संदेह है। उनका अस्तित्व। हर कानून। हर नीति।'' उन्होंने कहा, ''वक्फ संशोधन विधेयक केवल एक विधायी प्रस्ताव नहीं है। यह एक आईना है। और इसमें जो हम देखते हैं, उससे हम सभी को परेशान होना चाहिए - चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म हो या फिर किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक के लिए अधिकारों को फिर से लिखा जा सकता है, तो वे सभी के लिए फिर से लिखे जा सकते हैं।''

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कल्याणकारी उपायों की उन्हें जानकारी देने के लिए शुक्रवार को महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने यहां 1, अणे मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से सभी जिलों के लिए 'महिला संवाद' जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ''ये वाहन सभी जिलों में जाएंगे और महिलाओं के लिए सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे तथा संवाद की सुविधा प्रदान करेंगे।'' बयान में कहा गया है, ''इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें उन संसाधनों एवं अवसरों से जोड़ना है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को मुहैया कराये जा रहे हैं।''

कार्यक्रम में, महिलाओं को संबोधित मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र भी जारी किया गया। संवाद के दौरान प्राप्त होने वाली समस्याओं का विभिन्न स्तरों पर त्वरित समाधान किया जाएगा। इससे सरकार को महिलाओं के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार, अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि संवाद का आयोजन राज्य में करीब 70,000 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें दो करोड़ से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों को अभियान के दौरान वीडियो फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए बड़ी टेलीविजन स्क्रीन वाले करीब 600 वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। अभियान के दौरान प्राप्त सुझावों को अधिकारियों द्वारा संकलित किया जाएगा।

उप्र : संभल में 70 अवैध चिकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई, 50 से अधिक मामले दर्ज

संभल/भाषा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले एक सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 70 झोलाछाप (अयोग्य) चिकित्सकों और अवैध चिकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई की और मामले में 50 से अधिक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सीएमओ तरुण कुमार पाठक ने संवाददाताओं को बताया कि जिले के तीन सेक्टरों संभल, गुन्नौर और चंदौसी में अपंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, लगभग 70 अवैध अस्पताल और क्लीनिक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा, इन अवैध प्रतिष्ठानों को चलाने वाले 50 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पाठक ने कहा कि अवैध रूप से चल रहे और बिना किसी पंजीकरण के कार्य कर रहे झोलाछाप चिकित्सकों और प्रयोगशाला के खिलाफ कार्रवाई की गयी। पिछले एक हफ्ते में हमने जिले के तीन सेक्टरों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। हमारे पास पंजीकृत नहीं होने वाले 70 अस्पतालों और क्लीनिकों की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया है और 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

असम पंचायत चुनाव में 348 सीटों पर निर्विरोध फैसला, 325 पर राजग की जीत : हिमंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में पंचायत प्रणाली की कुल 348 सीटों पर निर्विरोध फैसला हुआ है, जिनमें से 325 सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने जीती हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान दो चरणों में दो मई और सात मई को कराए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल है। भाजपा नेता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया, ''अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, राजग ने पहले ही 37 जिला परिषद (35 भाजपा और दो अगप) और 288 आंचलिक पंचायत (259 भाजपा और 29 अगप) सीटें निर्विरोध हासिल कर ली हैं।'' शर्मा द्वारा साझा किए गए चार्ट के अनुसार, निर्दलीय उम्मीदवारों ने आंचलिक परिषद की 15 सीटें निर्विरोध हासिल की हैं जबकि कांग्रेस ने नौ और एआईयूडीएफ ने एक सीट निर्विरोध जीती है। शर्मा ने कहा, ''यह असम के राजनीतिक इतिहास में एक विशाल और अभूतपूर्व जनादेश है। यह राजग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति असम के लोगों के असीम विश्वास और अपार प्रेम को दर्शाता है।'' उन्होंने कहा, ''हमें विश्वास है कि जब अंतिम चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, तो यह संख्या और भी प्रभावशाली होगी।''

महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर रही है डब्ल्यूपीएल : मंधाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पिछले छह साल में महिला क्रिकेट के लिए काफी काम किया है और पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर शुरू हुई महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को सशक्त कर रही है।

मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) ने डब्ल्यूपीएल खिताब अपनी झोली में डाला था जो आरसीबी की कैबिनेट में एकमात्र ट्रॉफी है।

महाराष्ट्र के सांगली जिले की इस स्टार क्रिकेटर का कहना है कि अभी तो डब्ल्यूपीएल के तीन चरण ही खेले गए हैं लेकिन इसका असर घरेलू क्रिकेट और लड़कियों पर साफ दिखने लगा है। उन्होंने कहा, ''अंडर-19 टीम की खिलाड़ियों में बड़ा बदलाव आया है, उन्हें इतनी सारी चीजें पता हैं जो हम अपने दिनों में नहीं जानते थे। इसलिये लीग के आने से काफी विकास हुआ है। अब टीवी पर भी महिला क्रिकेट का प्रसारण होता है, सब भारतीय महिला टीम को जानते हैं। बीसीसीआई ने पिछले छह साल में महिला क्रिकेट के लिए बहुत काम किया है। '' मंधाना ने दुबई में 'सिटी क्रिकेट अकादमी' के लांच के मौके पर चुनिंदा मीडिया से वर्चुअल बातचीत में कहा , ''पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यूपीएल किस तरह से आगे बढ़ा है, इसे देखने के लिए कितनी सारी लड़कियां आ रही हैं, आप स्पष्ट बदलाव देख सकते हैं। छोटी छोटी लड़कियां भी हमारे पास आ रही हैं और वे क्रिकेटर बनना चाहती हैं जो बहुत अच्छी चीज है। काफी माता-पिता अपनी बच्चियों को अकादमी में भेज रहे हैं ताकि वे डब्ल्यूपीएल में खेल सकें। '' उन्होंने कहा, ''महिला क्रिकेट अब लोकप्रिय हो रहा है। टी20 क्रिकेट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए डब्ल्यूपीएल भी दर्शकों का काफी मनोरंजन कर रहा है। डब्ल्यूपीएल उसी तरह काम कर रहा है जैसा आईपीएल ने पुरुष क्रिकेट के लिए किया था। घरेलू क्रिकेट पर भी इसका असर दिख रहा है, लड़कियां डब्ल्यूपीएल खेलकर भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना चाहती हैं। '' मंधाना काफी समय से खुद की अकादमी बनाने पर विचार कर रही थीं लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण ऐसा नहीं कर पा रही थीं। फिर इस बारे में असम के पूर्व क्रिकेटर और ब्रिटेन में बसे मशहूर कोच डॉन भगवती से भी उनकी बातचीत हुई जिन्होंने लीस्टर में बहुत साल पहले अपनी अकादमी शुरू की थी। अब दुबई के बाद भगवती की योजना भारत में भी इसी तरह की अकादमी शुरू करने की है। अकादमी में युवा प्रतिभाओं को तराशने में डॉन की पत्नी का अनुभव भी काम आता है जो इंग्लैंड की क्रिकेटर रह चुकी हैं।

मंधाना ने इस अकादमी में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कहा, ''हम अकादमी में महिला क्रिकेट के विकास पर ध्यान लगाना चाहते थे कि सिर्फ उनके कौशल ही समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए। कुछ अकादमियां केवल कौशल पर ध्यान लगाती हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हों। इसमें खेल विज्ञान सहित पोषण का ध्यान रखा जाए इसलिए पोषण विशेषज्ञ भी होंगे।

जीतू राय ने विश्व कप से पहले शिविर में मुझे कुछ उपयोगी सुझाव दिए थे: सुरुचि सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। निशानेबाज सुरुचि सिंह की अंगुलियों में सटीक निशाना साधने की प्रतिभा पहले से ही थी लेकिन राष्ट्रीय शिविर में पिस्टल के दिग्गज जीतू राय से मिले सुझाव से वह दक्षिण अमेरिका में आईएसएसएफ विश्व कप में कई स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही।

भारत की शीर्ष घरेलू प्रतियोगिताओं में कई पदक जीतने वाली इस 18 साल की निशानेबाज को भारतीय निशानेबाजी में अगली बड़ी खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सुरुचि ने अपनी प्रतिभा और धैर्य से काफी प्रभावित किया है। उन्हें अपनी घरेलू सफलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए थोड़ी 'सलाह' की जरूरत थी और ऐसे में उन्हें जीतू से मार्गदर्शन मिला। इस सुझाव के बाद उन्होंने बेहद ही कम समय में आईएसएसएफ विश्व कप में दो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। सुरुचि ने लीमा से कहा, '' जीतू ने मुझे कुछ सुझाव दिए, जिनसे मुझे यहां बहुत मदद मिली और खेल में आगे बढ़ने के लिए ये सलाह महत्वपूर्ण हैं। मैंने उनकी सलाह का पालन किया और इसका फल मुझे मिला।'' वर्तमान में राष्ट्रीय टीम के पिस्टल कोचों में से एक जीतू को सुरुचि लंबे समय से जानती हैं। जब झज्जर की निशानेबाज ने अपने राष्ट्रीय कोच के रूप में सेना के इस पूर्व निशानेबाज को चुना तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सुरुचि के पिता भी सेना से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जीतू को अपने समय के दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल निशानेबाजों में से एक माना जाता था और जिन्होंने शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में कई स्वर्ण पदक जीते है। अपनी विनम्रता के लिए पहचाने जाने वाले इस पूर्व निशानेबाज ने कहा कि सुरुचि के पास अच्छी तकनीक है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है।

सुविचार

सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्म संतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया, जिसके लिए आप सक्षम हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

फीस बढ़ोतरी: पुख्ता समाधान क्या है?

राष्ट्रीय राजधानी समेत कई शहरों में अभिभावक निजी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं, निजी स्कूलों पर मनमानी फीस लेने और उनके बच्चों को अलग बैठाकर मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं, निजी स्कूलों का तर्क है कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए कम फीस में संचालन करना संभव नहीं है। कहीं नेतागण बयान दे रहे हैं, कहीं अभिभावक कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसी खबरें हर साल पढ़ने को मिलती हैं। आखिरकार, बढ़ी हुई फीस में मामूली छूट मिलने पर अभिभावक मान जाते हैं। दोनों ही पक्षों के अपने तर्क होते हैं, जिन्हें वे सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या का कोई पुख्ता समाधान नहीं होता। बेशक, महंगाई बढ़ने से आम लोगों की कमाई इतनी नहीं रही कि वे बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ाकर अपने लिए कुछ बचत कर सकें। सवाल है– क्या बच्चों की पढ़ाई महंगे निजी स्कूल में कराना ही एकमात्र विकल्प है? हमने अपने सरकारी स्कूलों को क्यों बिसरा दिया? सरकारी स्कूलों की यह छवि किसने बनाई कि वे सिर्फ गरीब बच्चों के लिए खोले गए हैं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई सफल नहीं हुआ? लोग निजी स्कूलों की फीस में कटौती कराने के लिए एकजुट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं। वे ऐसा जरूर करें, यह उनका अधिकार है, लेकिन इतनी ऊर्जा सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने में क्यों नहीं लगाते? लोग इतने ही प्रयास सरकारी स्कूलों के लिए करते तो आज उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता।

प्रायः सरकारी स्कूलों के संबंध में कुछ शिकायतें होती हैं, जैसे- वहां सुविधाओं का अभाव है, पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अच्छे नहीं आते हैं। ये ऐसी शिकायतें हैं, जिन्हें अभिभावक आसानी से दूर कर सकते हैं।

प्राय: सरकारी स्कूलों के संबंध में कुछ शिकायतें होती हैं, जैसे– वहां सुविधाओं का अभाव है, पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अच्छे नहीं आते हैं। ये ऐसी शिकायतें हैं, जिन्हें अभिभावक आसानी से दूर कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में संसाधनों की कमी है तो अभिभावक और स्थानीय लोग थोड़ा–थोड़ा योगदान देकर उनकी पूर्ति कर सकते हैं। यह निवेश वर्षों तक फायदा देगा। बात कड़वी है, लेकिन सच है कि लोग जानेमाने निजी स्कूलों की फीस का एक चौथाई हिस्सा भी सरकारी स्कूलों में नहीं लगाना चाहते। अगर लोग एकजुट होकर यह जिम्मेदारी संभाल लें तो संसाधनों की कमी बहुत जल्दी दूर हो सकती है। रही बात पढ़ाई के स्तर की, तो उसे भी बेहतर बनाया जा सकता है। समस्त अभिभावक सरकारी स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करें। उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करें। जब लोग एकजुट होंगे तो जनप्रतिनिधियों को आना ही होगा। अगर नहीं आएंगे तो अगले चुनाव में नुकसान उठाएंगे। बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा की जाए, जिन पर काम करने से पढ़ाई का स्तर सुधर सकता है। शिक्षक, अभिभावक और जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया के जरिए लगातार संपर्क में रहें। वे वॉटसऐप पर ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें स्थानीय सरकारी स्कूल की बेहतरी पर ही चर्चा हो। इससे पढ़ाई का स्तर जरूर सुधरेगा। फिर भी किसी बच्चे को अतिरिक्त तैयारी की जरूरत हो तो कई ऐप ऑनलाइन मार्गदर्शन देते हैं। उनकी मदद ले सकते हैं। आज सरकारी स्कूलों की जो हालत है, उसके लिए हम सब कहीं–न–कहीं जिम्मेदार हैं। जब चुनावों का मौसम आता है, तब कितने लोग सरकारी स्कूलों के मुद्दे उठाते हैं? कितने नेता हैं, जो यह कहने का साहस दिखाते हैं कि हम जिस इलाके से वोट लेंगे, वहीं के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तो यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से ही शिक्षा दिलाएं। इसके लिए जनता आवाज उठाए। ये स्कूल सिर्फ सरकार के नहीं, आपके भी हैं।

ट्वीटर टॉक

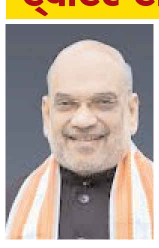

श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म के नौवें गुरु के रूप में अधर्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ समाज को जागरूक कर सिख धर्म को स्व–संस्कृति की रक्षा का पर्याय बनाया। आज उनके प्रकाश पर्व पर उनका स्मरण कर नमन करता हूँ।

–अमित शाह

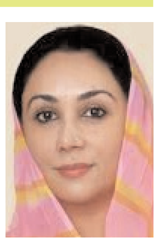

राजस्थान प्राचीन, सांस्कृतिक एवं अमूल्य धरोहरों का एक अनूठा समागम है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आइए, हम अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की अनमोल धरोहरों को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोने का संकल्प लें।

–दीया कुमारी

हमारा गौरवशाली इतिहास, सभ्यता, सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज़ हमारी धरोहर हैं तथा हमारी पहचान हैं। विश्व धरोहर दिवस पर इनके संरक्षण का संकल्प लें। आने वाली पीढ़ी इनसे जुड़ाव महसूस करे, गर्व करे और इन्हें आगे बढ़ाए, यही हमारी सच्ची विरासत होगी।

–अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

सद्कर्मों से सुरक्षा

एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। व्यापार के सिलसिले में उसका बाहर आना–जाना लगा रहता था। एक बार वह परदेस से लौटते समय धन साथ होने के कारण तीन–चार पहरेदार साथ लाया। नगर के पास पहुंचते ही उसने सोचा कि अब क्या डर, पहरेदारों को घर ले जाने से भोजन कराना पड़ेगा, इसलिए उन्हें यहीं से विदा कर दिया। कुछ ही दूर गया था कि डाकुओं ने घेर लिया। तभी उसने उनमें दो को पहचान लिया, जो कभी उसकी दुकान पर काम कर चुके थे। नाम सुनकर उन्होंने भी सेठ को पहचान लिया और बाकी साथियों को लूटने से मना कर दिया। सेठ सुरक्षित घर पहुंचा। वह सोचने लगादो घड़ी के अच्छे कर्म डाकुओं से जान बचा सकते हैं।

सामयिक

संविधान एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस भी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके पास कोर्ट जाने का विकल्प हमेशा मौजूद है। पहले भी कोर्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसलों को कोर्ट पलट चुका है। आखिरी बार 2017 में उत्तराखंड में भी ऐसा हो चुका है। तब कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलटकर हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था। ममता की बंगाल में जिस तरह की छवि है उससे वो कोर्ट के साथ जमीन पर भी लड़ाई शुरू कर सकती हैं।

क्या बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन?

अशोक भाटिया
मोबाइल : 9221232130

जब लोकतंत्र के चौराहे पर धुएं की लकीरें उठने लगें और सन्नाटा बाजारों में पसरे, तो समझिए कि कहीं कुछ बहुत ग़लत घट रहा है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इन दिनों ऐसी ही बेचैनी से गुज़र रहा है। सुती, समसेरगंज, धुलियान और जंगीपुर की गलियों में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं, एक गहरे तनाव की आहट है। शुक्रवार (11 अप्रैल) से शुरू हुई हिंसा में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है, और कई घायल हैं। इंटरनेट ठप है, दुकानें बंद हैं, और सुरक्षाबल हर मोड़ पर तैनात हैं। इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है पर क्या सिर्फ बंदूकों और बैरिकेड्स से भरोसे की बहाली हो सकती है? यह सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति, कानून–व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं के बीच जारी रस्साकशी की एक और कड़ी बनती जा रही है। बंगाल में हिंसा नई बात नहीं। कभी महिलाओं को सरे आम सड़क पर पीटा जाता है। तो कहीं पंचायत के कुछ लोग 'कंगारू कचहरी' लगातर इंसाफ करते है। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अटकलें लग रही हैं। बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आकर रिपोर्ट दे चुके हैं। बोस ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा देश के गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।

कांग्रेस, ढ्वउ या अन्य किसी विपक्षी दल शासित राज्य में बलात्कार की वारदात हो तो बीजेपी के नेता सुबह शाम उस प्रदेश को मुख्यमंत्री को कोसते हुए इस्तीफा मांगने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब बीजेपी शासित राज्य में बलात्कार की कोई घटना होती हो तो उसी तर्ज पर विपक्ष उस मामले को इश्यू बनाकर एकजुट हो जाता है। ऐसे में इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सभी दलों के नेता अपने अपने राज्यों में हुई हैवानियत पर सियासी नफे नुकसान के हिसाब से चुप्पी साध लेते हैं। मानवीय दृष्टी से देखा जाय तो बलात्कार किसी महिला के सीने पर लगा वो जख्म होता है, जो कभी नहीं भरता। जिस कोख से बच्चा जन्म लेता है जब उससे हैवानियत होती है तो सिर्फ मानवता ही शर्मसार नहीं होती, पुरुषों की कथित समाज की ठेकेदारी पर भी सवाल उठते हैं। धरने–प्रदर्शन होते हैं। कैंडल मार्च निकलता है। आरोप लगते हैं। इस्तीफा मांगा जाता है। प्रशासन सतर्क, पुलिस मुस्तैद और जनता भी जागरूक दिखती है पर वो चुल्लूभर पानी कहीं नहीं दिखता जिसमें ऐसा महापाप करने वाले डूब मरते। कोलकाता की डॉक्टर से हुई हैवानियत का मामला इतना तूल पकड़ लेगा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई दावानल का रूप ले लेगी। ये तो किसी ने सोचा भी न होगा। वरना 2012 के निर्भया कांड से लेकर 2024 के कोलकाता की डॉक्टर बेटी 'अभया' के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश की संवेदनाएं जागने में 12 साल नहीं लगते।'निर्भया' और 'अभया' के मामलों के बीच के 12 सालों में देश में हजारों बलात्कार हुए। लेकिन उन लड़कियों और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा आंदोलन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भी समाज और सरकार दोनों को देना होगा।

बीजेपी कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टिप्पणी इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाती है। अब समय आ गया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जाए। बीजेपी का ये रिएक्शन राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा न्यूज़ एजेंसी 'पीटीआई' के लिए लिखे गए एक विशेष हस्ताक्षरित लेख के बाद आई। जिसमें उन्होंने कोलकाता में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर बात की और महिलाओं के खिलाफ जारी अपराधों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर भयभीत दिख रही हैं। इसलिए लगातार बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ 'आग' उगलते हुए बहुत कुछ जल जाने की धमकी दे रही है। वहीं राष्ट्रपति की राय पब्लिक डोमेन में आने के बाद अटकले लग रही है कि क्या ममता दीदी की कुर्सी छीन ली जाएगी और उनकी सत्ता जाने वाली है? यह सबसे बड़ा सवाल दिल्ली से लेकर बंगाल तक हर किसी के दिमाग में तेजी से घूम रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आक्रोश जाहिर करने के साथ ही इस पर अंकुश लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि "बस! बहुत हो चुका। अब वो समय आ गया है कि भारत ऐसी 'विकृतियों' के प्रति जागरूक हो और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को 'कम शक्तिशाली', 'कम सक्षम' और 'कम बुद्धिमान' के रूप में देखती है।' राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं। भारत की सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं। वो एक महिला हैं। देश की हर बेटी उनमें अपनी मां की छवि देखती है। ऐसे में कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति के बयान से मामले की गंभीरता और गहराई को समझा जा सकता है।

एक दशक से अधिक समय से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेता बीते 10 सालों से ये कहते नहीं थक रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नया नहीं किया। देश में जो कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया। नेहरू–गांधी परिवार ने किया। उनकी नीतियों ने किया। मोदी जो कर रहे हैं वो कांग्रेस का विजन था। उसका सपना कांग्रेस नेताओं ने देखा था। इसके बाद बीजेपी नेता अपनी सरकार के कामकाज गिनाते हुए कांग्रेस के आरोपों का काउंटर करते हैं। अब समझने की बात ये है कि कांग्रेस ने भारत में अपने लंबे शासन काल में कई राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगाकर बर्खास्त किया था। अब कांग्रेस नेताओं की उस बात पर गौर करें जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी और मोदी, कांग्रेस के कामों को कॉपी–पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी, अब बंगाल का किला ढहाने के लिए उसी अस्त्र का इस्तेमाल तो नहीं करने जा रही, जिससे कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों ने कई राज्यों में विपक्ष की सरकारों को वहां की कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर गिरा दिया था। शायद यही डर 'दीदी' यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगने लगा होगा कि जिस तरह बीजेपी नेता, टीएमसी की सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसे में महिला राष्ट्रपति की राय को आधार बनाकर कहीं केंद्र की सरकार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके उनकी सरकार तो नहीं गिरा देगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ जाने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है।

संविधान एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस भी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके पास कोर्ट जाने का विकल्प हमेशा मौजूद है। पहले भी कोर्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसलों को कोर्ट पलट चुका है। आखिरी बार 2017 में उत्तराखंड में भी ऐसा हो चुका है। तब कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलटकर हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था। ममता की बंगाल में जिस तरह की छवि है उससे वो कोर्ट के साथ जमीन पर भी लड़ाई शुरू कर सकती हैं। राज्य में पद यात्रा या धरने और रैलियां करके ये संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। गौरतलब है कि बंगाल में आखिरी बार 29 जून 1971 को राष्ट्रपति शासन लगा था। नई विधानसभा के गठन के बाद 20 मार्च 1972 को राष्ट्रपति शासन हटा था। कुल मिलाकर बंगाल में अब तक चार बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1 जुलाई 1962 को नौ दिन के लिए, दूसरी बार 20 फरवरी 1968 में करीब एक साल के लिए और तीसरी बार 19 मार्च 1970 में करीब एक साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। सत्ता, सेवा का साधन है या कुछ और? इस सवाल पर नेताओं की अपनी अलग–अलग राय और दृष्टि हो सकती है। राहुल गांधी ने एक सियासी किस्सा सुनाते हुए कभी कहा था – 'सत्ता जहर होती है।' ऐसे में जब बंगाल का मामला तूल पकड़ रहा है, तो एक बार फिर सत्ता को गिराने वाली ताकत की चर्चा तेजी हो गई है। धयान देने वाली बात यह भी है कि 1994 में आए सुप्रीम कोर्ट के एस।आर। बोम्मई बनाम भारत संघ फैसले ने अनुच्छेद 356 के उपयोग की सीमाएं तय कर राखी है । कोर्ट ने साफ किया कि इस प्रावधान का इस्तेमाल सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य प्रशासनिक असफलता या कानून–व्यवस्था की समस्या राष्ट्रपति शासन का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। साथ ही, धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना है और इसे कमजोर करने के नाम पर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।अब मुर्शिदाबाद की हिंसा और उसके बाद उठी राजनीतिक मांगों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। हालांकि, राष्ट्रपति शासन जैसी बड़ी संवैधानिक कार्रवाई के लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या क्षेत्रीय हिंसा पर्याप्त नहीं है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार, जब तक राज्य सरकार स्पष्ट रूप से संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है, तब तक अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल अंतिम उपाय के तौर पर ही किया जा सकता है।

नजरिया

बिहार चुनाव : मगध की सत्ता का दिल्ली तक होगा असर

बाल मुकुन्द ओझा
मोबाइल : 8949519406

बिहार में सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पाले में होते हैं उसी की सरकार बनती है। आश्चर्य की बात तो यह भी है की दोनों खेमों की प्रमुख पार्टियां भाजपा और राजद है मगर सीएम की कुर्सी हर बार नीतीश के पास रहती है जबकि उनकी पार्टी जेडी यू वहां सीटों के लिहाज़ से तीसरे नंबर की पार्टी है।

सियासी समीक्षकों का कहना है इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का असर राष्ट्रीय राजनीति पर निश्चित रूप से पड़ेगा। यह बात इसलिए भी कही जा रही है कि मोदी सरकार मौजूदा दौर में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैशाखियों पर टिकी है। यह कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि मगध में सता की हनक दिल्ली तक शिद्दत से महसूस की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडी यू के पास लोकसभा की 12 सीटें है। यदि नीतीश और मोदी बिहार का चुनाव हार जाते है तो इसका असर नीतीश की पार्टी पर पड़ेगा और आरजेडी सुप्रीमों को विश्वास है उस स्थिति में नीतीश के गिरते स्वास्थ्य का फायदा उठाकर उनकी पार्टी में सेंध लगाने में सफल हो जायेंगे। हालाँकि हाल फिलहाल यह दूर की कौड़ी है। बिहार चुनाव को लेकर समय एनडीए एकजुट है। लालू के बेटे तेजस्वी ने कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गाँधी से मुलाकात कर बिहार चुनाव की रणनीति पर बात की है। लालू और उनके बेटे तेजस्वी को विश्वास है कि यदि बिहार फ़तेह कर लिया तो नीतीश की पार्टी में भगदड़ मच जाएगी और अंततोगत्वा इसका सीधा नुक्सान मोदी सरकार को होगा। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी से भटकाया जा सकता है। एनडीए के सूत्रों का कहना है सपना लेने का अधिकार सब को है। उनका सपना तो टूटेगा ही साथ ही एनडीए फिर बिहार में अपनी सरकार बना लेगा । बहरहाल चुनावी सरगर्मियां बिहार में बहुत तेजी पर है। यह चुनाव एक राज्य का चुनाव न होकर राष्ट्रीय स्थिति पर सियासी तस्वीर बदलने वाले चुनाव के रूप में लड़ा जा रहा है ।

वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव होगा। देखना होगा कि नीतीश मुस्लिम मतदाताओं का वोट अपनी झोली में ले जाते है या नहीं। वक्फ विधेयक के चलते मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे से पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरों की कमी हुई है। नीतीश को मुस्लिम वोटों का नुक्सान होने का अंदेशा है मगर कहा जा रहा है इसकी भरपाई भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी से हो जायेगा। बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल अक्टूबर–नवंबर में होना है। बिहार के दो प्रमुख चुनावी मोर्चे महागठबंधन और एनडीए ने सत्ता पर काबिज होने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। वर्तमान सरकार का कार्यकाल इस साल यानी 2025 में 22 नवंबर तक है। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे। बिहार में एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से होगा जिसका नेतृत्व लालू और तेजस्वी की बाप बेटे की जोड़ी के हाथ में है। इस गठजोड़ में कांग्रेस सहित वामपंथी पार्टियां शामिल है। दिल्ली में जीरो हैट्रिक के बाद बिहार में कांग्रेस को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। लालू ने अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की सार्वजनिक घोषणा कर रखी है। बिहार में येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए लालू यादव की छटपटाहट बस देखते ही बनती है। राजद अध्यक्ष लालू यादव अब बूढ़े हो चुके है और चाहते है उनकी विरासत के साथ बिहार की राजगद्दी बेटे तेजस्वी को मिले। बिहार की सियासत वाकई बड़ी अजब गजब है। नीतीश सब के लिए अपरिहार्य हो गए है। बिहार में दो प्रमुख सियासी खेमे हैं। एक महागठबंधन तो दूसरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दोनों ही खेमों में इस बात को लेकर हमेशा रस्साकशी भी चलती रहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके खेमे में आ जाएं और बिहार की कमान संभालें।

बिहार में सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पाले में होते हैं उसी की सरकार बनती है। आश्चर्य की बात तो यह भी है की दोनों खेमों की प्रमुख पार्टियां भाजपा और राजद है मगर सीएम की कुर्सी हर बार नीतीश के पास रहती है जबकि उनकी पार्टी जेडी यू वहां सीटों के लिहाज़ से तीसरे नंबर की पार्टी है। समूचे देश की निगाहें चुनावी नतीजों और उसके बाद होने वाले सियासी और सामाजिक प्रभावों पर लगी हुई हैं। एनडीए चुनाव जीता तो मोदी का इकबाल और बुलंद होगा। केंद्र के स्तर पर रुके हुए कई जटिल सुधारों के फैसले लेने की गति तेज हो सकती है। वहीं आरजेडी नीत महागठबंधन विजयी हुआ तो मोदी की स्थिति कमजोर होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

बाह्यग्रह पर जैविक गतिविधि से रात्रि आकाश को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है: खगोलशास्त्री

नई दिल्ली/भाषा। खगोलशास्त्री निक्कू मधुसूदन के मुताबिक सौरमंडल के बाहर जैविक गतिविधि के साक्ष्य से रात्रि आकाश को देखने का तरीका मौलिक रूप से बदल सकता है। उन्होंने कहा कि यह नजरिया आकाश को भौतिक, निर्जीव आकाश के रूप में देखने से लेकर इसे ''जीवन युक्त आकाश'' के रूप में देखने तक बदल सकता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खगोलशास्त्री और बाह्यग्रहीय विज्ञान के प्रोफेसर मधुसूदन एक अध्ययन दल के प्रमुख अनुसंधानकर्ता हैं। इस दल ने पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बाह्यग्रह के2-18बी पर डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड अणुओं के होने का संकेत तलाशा है।

विज्ञान जगत में माना जाता है कि पृथ्वी पर इन अणुओं को समुद्री जीवों द्वारा उत्पादित माना जाता है और इन्हें बाह्यग्रहों पर जीवन या जैविक अधिवास का शुरुआती संकेत मानते हैं। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स' में प्रकाशित अनुसंधान के परिणाम सौरमंडल के बाहर जीवन के अब तक के सबसे पुख्ता संकेत हैं। मधुसूदन ने बताया, ''यह पूरी तरह से संभव है कि अगर हम (के2-18 बी) पर कुछ और अवलोकन करें, तो कुछ वर्षों में हम पुख्ता तरीके से इन अणुओं का पता लगा सकते हैं।''

वर्तमान में यह अध्ययन 'थ्री-सिग्मा' महत्व के साक्ष्य प्रदान करता है। यह वस्तुनिष्ठ गणना के लिए इस्तेमाल सांख्यिकीय शब्द है, जो 99.7 प्रतिशत विश्वास को दर्शाता है कि अध्ययन के परिणाम 'अनायास मिली' सफलता नहीं हैं।

मधुसूदन ने कहा, ''थ्री सिग्मा का अर्थ है कि आपके पास अब भी 0.3 प्रतिशत संभावना है कि यह सांख्यिकीय संयोग है – संयोग होने की संभावना लगभग एक हजार में से तीन है।''

खगोलभौतिकीविद के अनुसार, यद्यपि इस दर्जे की वास्तुनिष्ठ गणना को ''सम्मानजनक'' रूप से देखा गया। हालांकि, जब बात किसी वैज्ञानिक परिणाम की आती है, जिसके व्यापक निहितार्थ होते हैं – जैसे कि 'हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते' – तो 'आपको वास्तव में, पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहिए'।

मधुसूदन ने कहा, ''जब आपको बड़ी सफलताएं मिलती हैं, बड़े प्रतिमान बदलाव होते हैं, तो आप वास्तव में बहुत आश्वस्त होना चाहते हैं, क्योंकि इससे विज्ञान और समाज का स्वरूप मौलिक रूप से बदल जाता है।'' उन्होंने कहा, ''तो, पुख्ता माप यह है कि हम इस स्तर तक सुनिश्चित होना चाहते हैं कि अनायास हुई खोज की संभावना दस लाख में एक भाग से भी कम हो, जो सांख्यिकीय अप्रत्याशित घटना या ''सिर्फ संयोग'' की बहुत, बहुत, बहुत छोटी संभावना है।

विरोध प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने को पटना में नेशनल हेराल्ड से संबंधित कथित धन शोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुतला जलाया।

अमेरिकी कानून के उल्लंघन का प्रयास करने वाले छात्रों को सजा भुगतनी होगी: अमेरिकी विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कानून के उल्लंघन का प्रयास करने वाले छात्रों को सजा भुगतनी होगी, जिसमें देश से निर्वासित किया जाना भी शामिल है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरिट मैकलियोड ने पीटीआई को डिजिटल माध्यम से दिए गए साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप प्रशासन आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम और 'एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट' (प्रवासी पंजीकरण अधिनियम) समेत आप्रवासन कानूनों को कठोरता से लागू कर रहा है।

मैकलियोड ने अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के सामने आ रहीं समस्याओं के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा, अगर आप कानून का पालन करते हैं तो अमेरिका आपको अवसर मुहैया कराएगा। लेकिन कानून का उल्लंघन करने वालों को परिणाम भुगतने होंगे।

अमेरिका में भारतीय छात्र निर्वासन के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में भाग लेने से लेकर छोटे-छोटे कानूनी उल्लंघनों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर एफ-1 वीजा रद्द कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बृहस्पतिवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था, हमें पता है कि कई भारतीय छात्रों को अमेरिकी सरकार की ओर से उनके एफ-1 वीजा की स्थिति के बारे में सूचना मिली है, जो कि छात्र वीजा है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावास सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के संपर्क में हैं।

जायसवाल कई भारतीय छात्रों को ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की ओर से भेजे गए संदेशों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इन पत्रों में छात्रों के वीजा रद्द होने की आशंका के बारे में बताया गया है।

हालांकि मैकलियोड ने किसी खास मामले का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दंड से बचने के लिए अमेरिकी कानूनी व वीजा आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।

अवैध आव्रजन से जुड़े व्यापक मुद्दे पर, मैकलियोड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन आव्रजन कानूनों को कठोरता से लागू कर रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकी सरकार अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे कानूनों को तोड़कर प्रवेश करने वालों का स्वागत नहीं करेगी।

प्रार्थना

गुड फ्राइडे के अवसर पर मुरादाबाद के एक चर्च में नन प्रार्थना करती हुई।

'केसरी चैप्टर 2' सिर्फ फिल्म नहीं, एक अधूरा हिसाब और इंसाफ है : अक्षय कुमार

मुंबई/एजेन्सी

देश के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक जालियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में वकील सी. शंकरन नायर की भूमिका निभा रहे अभिनेता अक्षय कुमार ने एक पोस्ट में बताया कि 'केसरी चैप्टर 2' सिर्फ फिल्म नहीं, यह एक अधूरा हिसाब और इंसाफ है। इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए अभिनेता ने बताया कि 'केसरी चैप्टर 2' की कहानी एक तूफान है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, कहानियां बहुत सुनी होंगी आपने, पर यह एक तूफान है। सी. शंकरन नायर की इस कहानी ने मुझे झकझोर दिया क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसी एक व्यक्ति ने पूरे ब्रिटिश अंपायर को अदालत में घसीट कर घुटनों पर ला दिया था।

अभिनेता ने बताया कि वह 'केसरी चैप्टर 2' सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भारतीय की हैसियत से कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, मैं 'केसरी चैप्टर 2' सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भारतीय के तौर पर कर रहा हूं। यह सिर्फ एक फिल्म नहींयह एक अधूरा हिसाब है, यह एक दर्दनाक याद है और आखिरकार हमें मिला इंसाफ है।

13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी फिल्म में अक्षय कुमार सी. शंकरन नायर की भूमिका में हैं, जो कोर्ट रूम में जलियांवाला का सच दुनिया के सामने लाने और ब्रिटिश राज के खिलाफ दहाड़ते नजर आएंगे। वहीं, आर माधवन वकील नविल मेककिनले के किरदार में हैं, जो ब्रिटिश राज की ओर से कोर्ट में अक्षय का सामना करते हैं। अनन्या पांडे अपने करियर में निभाए गए अब तक निभाए किरदार से अलग नजर आएंगी। वह पहली बार पर्दे पर इस तरह की गंभीर भूमिका में दिखेंगी। 'केसरी 2' में अनन्या पांडे वकील दिलरीत गिल के किरदार में हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 'ए' सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब है कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं, जो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के देखने के लिए ही सही माने गए हैं। जानकारी के अनुसार, बोर्ड ने फिल्म के कुछ दृश्यों में भी बदलाव किए। फिल्म की कुल लंबाई 2 घंटे, 16 मिनट है।करण सिंह त्यागी के निर्देशन में बनी 'केसरी चैप्टर 2: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग' का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस, केप ऑफ गुड फिल्म्स और लियो मीडिया ने किया है।

फिल्म में अक्षय कुमार, अभिनेता आर. माधवन, अनन्या पांडे के साथ रेजिना कैसेंड्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। 18 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म को दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

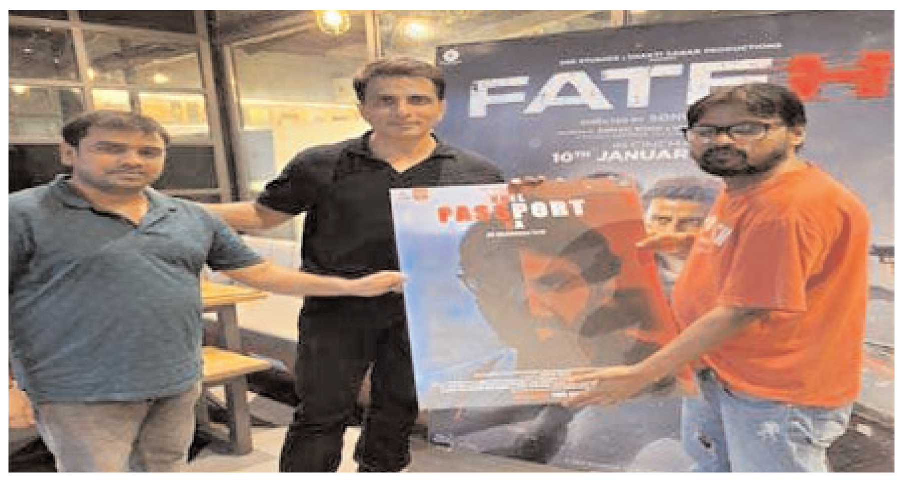

फिल्म 'खेल पासपोर्ट' का फर्स्ट लुक पोस्टर

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता सोनू सूद ने निर्देशक अर्जुन राज की आने वाली हिंदी फिल्म खेल पासपोर्ट का का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। सोनू सूद ने निर्देशक अर्जुन राज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है।

यह बयान फिल्म के लिए एक सकारात्मक संकेत है और दर्शकों में फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ा रहा है। फिल्म खेल पासपोर्ट का निर्माण हैप्पी क्राउड एंटरटेनमेंट, किंग केयान एंटरटेनमेंट और रजिया पठान के बैनर तले किया जा रहा है।

इस फिल्म को राजवंत शर्मा को-प्रोडयूस कर रहे हैं। अर्जुन राज के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लेखक अर्जुन राज, रंजू साइकोलोनी और रजिया पठान है। इस फिल्म में राजवंत शर्मा,गौरी शंकर,आरिफ सहडोल, हेरंब, मेघा सक्सेना, आनंद शर्मा, जेबा खान, अर्जुनराज ने अहम भूमिका निभायी है। डीओपी शक्ति सोनी, लखिंदर शॉ (लक्की) हैं। फिल्म का संगीत ह्रजु रॉय ने तैयार किया हैं। रवि बासनेट के रचित गीतों को अरिंदम चक्रवर्ती मंजीरा गांगुली ने मधुर आवाज से सजाया है। इस फिल्म का ट्रेलर 18 अप्रैल को डीआरजे रिकॉर्ड म्यूजिक से रिलीज होगा।

'जिंगुचा' में कमल हसन संग थिरकती दिखीं सान्या मल्होत्रा

मुंबई/एजेन्सी

'मिसेज़' की शानदार सफलता के बाद, सान्या मल्होत्रा अब मणिरत्नम की फिल्म 'ठग लाइफ' में एक नए, रंगीन अध्याय के साथ वापसी कर रही हैं। फिल्म का पहला और बहुप्रतीक्षित गाना 'जिंगुचा' रिलीज़ हो चुका है और सोशल मीडिया पर पहले ही तहलका मचा रहा है। यह गाना एक भव्य और हर्षोल्लास से भरी शादी के माहौल में सेट है, जिसमें सिनेमा के दिग्गज कमल हसन और सिलंबरासन टीआर नजर आते हैं और सान्या मल्होत्रा अपने ग्रेस और एनर्जी से इस जश्न को और खास बना देती हैं। हालांकि सान्या फिल्म में एक स्पेशल कैमियो में नजर आएंगी, लेकिन 'जिंगुचा' में उनकी मौजूदगी किसी भी तरह से मामूली नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस में जोश, ग्रेस और इलेक्ट्रिक अपील का अनूठा मेल है, जो इस फेस्टिव ट्रैक की रौनक को कई गुना बढ़ा देता है। शादी-थीम वाले इस गाने में सान्या ने युवा जोश और सिनेमाई लय से भरपूर परफॉरमेंस दी है, जो कमल हसन के सहज स्वैग और सिलंबरासन की अट्रैक्टिव एनर्जी को खूबसूरती से पूरक बनाती है। हालांकि यह एक सच्चा असेंबली मोमेंट है, लेकिन सान्या की स्क्रीन उपस्थिति और गतिशील डांस ने ट्रैक को अनदेखा करना मुश्किल है।

ए.आर. रहमान द्वारा रचित, जिंगुचा ने लोक-प्रेरित लय को आधुनिक साउंडस्केप के साथ जोड़ा है। कमल हसन द्वारा लिखे गए गीत एक चतुर, उत्सवपूर्ण स्पर्श लाते हैं, जबकि मणिरत्नम की सिग्नेचर विजुअल स्टोरीटेलिंग हर फ्रेम में समृद्धि की परतें जोड़ती है। सान्या ने तरल कोरियोग्राफी और निर्विवाद उपस्थिति के साथ स्क्रीन को रोशन किया, जिससे हमें ठग लाइफ की भव्यता की एक झलक मिलती है। 'मिसेज़' में दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद, सान्या ने एक बार फिर साबित किया है कि वह कितनी वर्सेटाइल और पावरफुल कलाकार हैं। '

अनुपम खेर ने 23 साल बाद पहनी डायरेक्टर की टी-शर्ट, बोले - 'तन्वी के किस्से सुनाता रहूंगा'

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता अनुपम खेर 'तन्वी द ग्रेट' के साथ 23 साल बाद निर्देशक की कुर्सी पर वापस आ चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि तन्वी की कहानी उनके दिल और आत्मा से निकली है। फिल्म से जुड़ी किस्से-कहानियां प्रशंसकों को सुनाते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर तस्वीर को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, मुझे 23 साल लग गए निर्देशक की टी-शर्ट दोबारा पहनने में! पहली फिल्म 'ओम जय जगदीश' को डायरेक्ट करना मुझे अच्छा लगा था। मेरा जो सामर्थ्य था, उस हिसाब से फिल्म बनाई थी, पर उस फिल्म की कहानी मेरी नहीं थी। 'तन्वी द ग्रेट' की कहानी मेरे दिल और आत्मा से निकली है, और फिर पिछले 23 साल में जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया भी है। अब फिल्म के रिलीज होने तक आपको 'तन्वी' से जुड़ी बातें, कहानियां और किस्से बताता रहूंगा! परेशान न होना! यह मार्केटिंग भी है और प्यार भी!

हाल ही में अनुपम खेर ने 'तन्वी द ग्रेट' मेकिंग की झलक दिखाई थी और बताया था कि हर कहानी के पीछे बेहतरीन कहानीकार होते हैं। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें वह कलाकारों को शॉटस के बारे में समझाते और टीम के साथ सीन पर चर्चा करते दिखे थे।

अनुपम की मोस्ट अवेटेड फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में सामने आया है। खास संदेश से सजी फिल्म के केंद्र में अनुपम खेर के 'दिल का टुकड़ा' तन्वी है। 'तन्वी द ग्रेट' की पहली झलक शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा था, फर्स्ट लुक, मैंने आज से लगभग चार साल पहले 'तन्वी द ग्रेट' फिल्म बनाने का फैसला किया था और फिर इसे लिखने और बनाने में मुझे चार साल लग गए! लेकिन अब धीरे-धीरे और ढेरों प्यार के साथ आप लोगों के साथ मेरे 'दिल के टुकड़े' को शेयर करने का समय आ गया है! अनुपम खेर के निर्देशन में तैयार फिल्म में ऑस्कर विजेता एम.एम. कीरावनी ने संगीत दिया है। फिल्म का निर्माण अनुपम खेर स्टूडियोज ने एनएफडीसी (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम) के साथ मिलकर किया है।

सोनी बीबीसी अर्थ पर 'व्हेयर द वाइल्ड मेन आर विद बेन फोगल' सीज़न-10, 21 से प्रसारित होगा

मुंबई/एजेन्सी

व्हेयर द वाइल्ड मैन आर विद बेन फोगल' सीज़न 10,21 अप्रैल से सोनी बीबीसी अर्थ पर प्रसारित होगा। सोनी बीबीसी अर्थ 'व्हेयर द वाइल्ड मैन आर विद बेन फोगल' के साथ दर्शकों को एक प्रेरणादायक यात्रा पर आमंत्रित कर रहा है। इस सीज़न के 12 दिलचस्प एपिसोड्स में बेन फोगल दुनिया के सबसे दूर-दराज़ इलाकों की यात्रा करते हैं और उन असाधारण लोगों के जीवन की झलक दिखाएंगे, जिन्होंने जान-बूझकर पारंपरिक जीवनशैली से हटकर एक अलग राह चुनी है। यह शो सोमवार, 21 अप्रैल को रात 9:00 बजे सोनी बीबीसी अर्थ पर प्रसारित होगा। इस सीरीज़ का दसवां सीज़न दर्शकों को ऐसे प्रेरणादायक किस्सों से रूबरू कराएगा जो व्यक्ति और प्रकृति के बीच गहरे संबंध और प्रकृति की शक्ति पर रौशनी डालते है। इस शो में बेन फोगल चुनिंदा एकांत स्थलों की यात्रा करते हैं और उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने समाज की पारंपरिक धारा से हटकर एक स्वतंत्र जीवन चुना है। इस शो के जरिये फोगल दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ प्राकृतिक दृश्यों की सैर कराते हैं और कैलिफ़ोर्निया के दुष्कर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार से मिलवाते हैं जो बिना सुविधाओं के जीवन जी रहा है। साथ ही, ओरेगन में एक तैरते हुए घर में रहने वाले व्यक्ति का असामान्य जीवन भी सामने ला रहे हैं।

यात्रा यहीं नहीं रुकती, दर्शक टस्कनी में पर्यावरण-के अनुकूल जीवन जीने वाले एक ब्रिटिश जोड़े की कहानी और ज़ाम्बिया में सफारी व्यवसाय चला रहे एक परिवार का प्रेरक जीवन देखेंगे। इसके अलावा, बेन फोगल दर्शकों को ग्रामीण इंग्लैंड में एक पूर्व पैराबैज (पैराट्रूपर) से मिलवाएंगे,जो प्रकृति की सहायता से अपने जीवन को फिर से संवार रहा है। एक आयरिश द्वीप पर पारंपरिक जीवनशैली को सहेज रहे एक जोड़े और थाईलैंड में कुत्तों को बचाने वाले एक व्यक्ति की दिल को छू लेने वाली कहानियां भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। इन अनुभवों के ज़रिए बेन फोगल यह दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग लोग अपने जीवन में प्रकृति से गहरे जुड़ाव को अपनाकर अनूठे तरीके से जीवन जी रहे हैं।

जैकलीन फर्नांडीज अभिनीत शो, है जुनून 16 मई से होगा प्रसारित

मुंबई/एजेन्सी

जैकलीन फर्नांडीज और नील नीतिन मुकेश अभिनीत शो है जुनून आगामी 16 मई से जियो हॉटस्टार पर प्रस्तुत किया जाएगा। शो है जुनून, एक उच्च-ऊर्जा, आने वाली उम्र का संगीत नाटक है जो मुंबई के प्रतिष्ठित एंडरसन कॉलेज के म्यूजिकल दुनिया पर आधारित है। अभिषेक शर्मा निर्देशित शो है जुनून में का निर्माण जियोहोटस्टार लैब्स के बैनर तले किया गया है इस शो में जैकलीन फर्नांडीज ने पर्ल और नील नितिन मुकेश ने गगन की भूमिका निभाई है, साथ है जुनून में सुमेध मुदगलकर, सिद्धार्थ निगम, युक्ति थरेजा, आर्यन कटोच, प्रियांक शर्मा, कुंवर अमर, मोहन पांडे, एलीशा मेयर, संचित कुंद्रा, सनातन रोच, देवांग्शी सेन, अनुषा मणि, भाविन भानुशाली, अर्नव मागू और युक्ति थरेजा मुख्य भूमिका में हैं। जैकलीन फर्नांडीस ने इस शो

को लेकर अपनी उत्साह जाहिर करते हुये कहा, है जुनून केवल संगीत या नृत्य की कहानी नहीं है; यह जुनून, प्रतिद्वंद्विता और उम्मीदों से भरी दुनिया में अपना स्थान खोजने के बारे में है। पर्ल की भूमिका निभाना एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव था मैं इस संगीतमय यात्रा में दर्शकों के शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।

नील नितिन मुकेश कहा, गगन आहूजा की भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों था। गगन एक गहन और अनुशासित संगीत किंवदंती हैं जो सुपरसोनिक्स की विरासत को अपने दिल के करीब रखते हैं। है जुनून में उनकी यात्रा एक कलाकार के जीवन के संघर्षों को दर्शाती है, जहाँ जुनून और सपनों को अक्सर अहंकार और आत्म-जुनून के रूप में गलत समझा जाता है। वास्तव में, यह आत्म-खोज और अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने की यात्रा है।

RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

जाति, भाषा, प्रांत और संप्रदायों का भेदभाव इतना जहरीला होता है कि वह न्याय, नीति, मानवता और कर्तव्य का बोध कभी नहीं होने देता। इनके बलबूते पर अयोग्य भी सत्ता की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। नीति शास्त्र कहता है कि अयोग्य के पास आई हुई सत्ता, सामर्थ्य और शक्ति सदैव लोगों के शोषण तथा उत्पीड़न का ही काम करती है। कमोबेश हम अपने देश के अनेक प्रांतों में और विश्व के अनेक देशों में यही स्थिति देख रहे हैं। यह कलयुग की करुण दर्दनाक कथा है।

मैसूरु रेल संग्रहालय ने विश्व धरोहर दिवस मनाया

भाप इंजन मॉडल का लाइव प्रदर्शन हुआ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु/दक्षिण भारत। दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) के मैसूरु मंडल के अंतर्गत मैसूरु रेल संग्रहालय ने शुक्रवार को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने इस साल की थीम– 'आपदा और संघर्ष–रोधी विरासत: विरासत की सुरक्षा के संबंध में कार्य' पर आधारित पोस्टर–मेकिंग, ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया।

मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मुदित मित्तल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में युवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। मित्तल ने कहा, 'युवा पीढ़ी को विरासत संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए।' उन्होंने छात्रों की रचनात्मकता की सराहना की और विरासत जागरूकता के अग्रदूत बनने का आह्वान किया। प्रतिभागियों ने शानदार कलाकृतियों के जरिए नवीन विचारों का प्रदर्शन किया। मुख्य आकर्षण हाथ से तैयार भाप इंजन मॉडल का लाइव प्रदर्शन था। अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधकों और विरासत संरक्षण विशेषज्ञों सहित वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने छात्रों के साथ बातचीत की और उनकी प्रतिभा को सराहा।

डीआरएम मित्तल ने समारोह का प्रेरणादायक ढंग से समापन करते हुए कहा, 'विश्व धरोहर दिवस हमें याद दिलाता है कि लचीलापन सिर्फ संरचनाओं में नहीं, बल्कि लोगों के सामूहिक प्रयासों में भी निहित होता है।' इस अवसर पर मैसूरु रेल संग्रहालय में आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क किया गया। मैसूरु रेलवे स्टेशन के पीएफ1 पर स्थित हेरिटेज गैलरी शनिवार को भी जनता के लिए खुली रहेगी।

विजयनगर स्थानक में सम्पन्न हुआ बाल संस्कार शिविर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक स्वाध्याय संघ द्वारा आयोजित दस दिवसीय बाल संस्कार शिविर का समापन समारोह गुरुवार को विजयनगर ज्ञानशाला समिति द्वारा आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 100 बच्चे व 8 अध्यापिकाएं शामिल हुईं। ज्ञानशाला के चेयरमैन कन्हैयालाल सुराणा ने आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कार स्कूलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रुपया, पैसा कमाने के लिए भले ही उच्च पढ़ाई की आवश्यकता हो, परन्तु उससे भी ज्यादा आज बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान एवं जैन संस्कार तथा जैनत्व की शिक्षा देने की जरूरत है, इसी से हमारा जीवन सुखमय व सीमित होते हुए परिवारों के साथ ख़ुशी से जीने में सहायक होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंदकुमार नाहर, पूर्व अध्यक्ष वसंतकुमार रांका ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कर्नाटक स्वाध्याय संघ से उपस्थित मीठालाल पटवा, महेन्द्रकुमार बम्बकी, कान्तिलाल गुगलिया का सम्मान किया गया। प्रबंधक पंकजकुमार मेहता, अध्यापिका समता बोहरा ने ज्ञानशाला के कार्यपद्धति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।

शिविरार्थियों द्वारा शिविर में लिए गए ज्ञान व संस्कारों पर आधारित अनेक प्रस्तुतियां दी।ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सुरेशचंद खाब्या ने धन्यवाद दिया। प्रबंधक शंकरलाल दक, रवीन्द्र कुमार गाँधी ने व्यवस्था संभाली इस अवसर पर युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्षा सहित संघ के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

बुद्ध का पवित्र दंत अवशेष 16 साल बाद श्रीलंका में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया

कोलंबो/भाषा। भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष को 16 साल के अंतराल के बाद शुक्रवार को श्रीलंका के केंद्रीय शहर कैंडी में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान से मिली।

श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह आयोजन 10 दिनों तक 27 अप्रैल तक जारी रहेगा तथा आम लोग अवशेष स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक देख सकते हैं।

बयान के अनुसार, भारत सहित 17 देशों के राजदूतों के लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत कैंडी तक उनके लिए ट्रेन से यात्रा का इंतजाम किया गया है।

कैंडी स्थित पवित्र दंत मंदिर के वरिष्ठ भिक्षु महावेला रत्नपाल ने संवाददाताओं को बताया कि हजारों बौद्ध श्रद्धालुओं के इस अवशेष का दर्शन करने के लिए आने की उम्मीद है।

यह दंत अवशेष इस द्वीपीय देश श्रीलंका के 74 प्रतिशत सिंहली बौद्ध बहुसंख्यकों के लिए विशेष आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।

रत्नपाल ने कहा, ''हजारों लोग दो दिन पहले से मंदिर तक पहुंचने वाले तीनों मार्गों पर कतार में खड़े हैं।''

ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, यह दंत अवशेष 1590 में कैंडी लाया गया था।

सेवा व सहयोग — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के बापूजीनगर क्षेत्र के निवासियों द्वारा बंडे महाकाली देवी उत्सव का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं अन्नदान कार्यक्रम की शुरुआत की। मुणोत ने जरूरतमंद बच्चों में शिक्षण सामग्री वितरित की। आयोजकों ने मुणोत का सम्मान किया।

पार्श्व लब्धि धाम में दस दिवसीय जयमल जैन संस्कार शिविर शुरू

देश भर से 600 से अधिक शिविरार्थियों ने लिया भाग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जय गच्छाधिपति, आचार्यश्री पार्श्वचंद्रजी, अणुप्पेहा ध्यान प्रणेता डॉ. पदमचंद्रमुनिजी, साध्वी शशिप्रभाश्रीजी, जैन समणी प्रमुखा डॉ. श्रीनिधिश्री आदि के सान्निध्य में पार्श्व लब्धि तीर्थ धाम में 18 अप्रैल को दस दिवसीय 79वाँ राष्ट्र स्तरीय जयमल जैन संस्कार शिविर का शुभारंभ आचार्य पार्श्वचन्द्रजी के मंगलाचरण से हुआ। डॉ. पदमचंद्रमुनिजी ने मोक्ष में पहुंचने के सरल उपाय बताने के साथ आगार धर्म और अणगार धर्म के बारे में बताया। शिविर में बच्चों से लेकर बड़ों ने आचार्य पार्श्वचंद्र के मुखारविंद से पहले व्रत स्थूल हिंसा का त्याग के प्रत्याख्यान ग्रहण किए।

प्रवचन के पश्चात अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के चेयरमैन मनिंदरजीतसिंह बिट्टा ने आचार्य पार्श्वचन्द्रजी एवं डॉ. पदमचंद्रमुनिजी के दर्शन किए और शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म जैम धर्म में हुआ, जैन धर्म का जीओ और जीने दो का सिद्धान्त सम्पूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है। तत्पश्चात वे शिविर उद्घाटन एवं ध्वजारोहण में सम्मिलित हुए। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाशचंद्र बोहरा ने शिविर के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस शिविर में कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, असम आदि राज्यों से करीब 600 शिविरार्थी सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह के लाभार्थी मिलापचन्द, संदीप, अनंत भंडारी परिवार, ध्वजारोहण के लाभार्थी लीलाबाई डॉ. भीकमचंद संकलेचा परिवार व हैदराबाद से आए अतिथियों व स्थानीय पदाधिकारियों ने किया। लाभार्थियों व अतिथियों का सम्मान जयमल जैन श्रावक संघ एवं जेपीपी जैन अणुप्पेहा ध्यान योग एकेडमी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्रकुमार मेहता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रेवंतमल नाहर, बेंगलूरु संघ के अध्यक्ष उत्तमचंद गादिया, मंत्री सुरेंद्रकुमार बेताला आदि ने किया।

जेके महावीरचंद चोरड़िया ने बताया कि इस अवसर पर शिविर के प्रमुख सहयोगी मीठालाल मकाणा एवं माणकचंद बोहरा, वरिष्ठ स्वाध्यायी रावतमल भुरट गुवाहटी, बेंगलूरु शाखा के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल कांकरिया की विशेष उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह के पश्चात 20 कक्षाओं में 25 से अधिक धार्मिक शिक्षकों द्वारा विधिवत रूप से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनोहरलाल डूंगरवाल ने किया।

माओवादी संघर्ष के दौरान किए गए जघन्य अपराधों के लिए कोई माफी नहीं: ओली

काठमांडू/भाषा। नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने कहा है कि देश में माओवादियों के विद्रोह के दौरान किये गए जघन्य और अमानवीय अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को कोई माफी नहीं दी जाएगी। उन्होंने यहां 'नेशनल एक्स–आर्मी एंड पुलिस ऑर्गनाइजेशन ऑफ नेपाल' (एनईएपीओएन) के सम्मेलन में यह बात कही।

सत्तारूढ़ सीपीएन–यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायिक व्यवस्था को 1996 से 2006 तक चले संघर्ष के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। ओली ने संघर्ष–काल के अपराधों की जांच करने और न्याय प्रदान करने में दो न्यायिक निकायों -- 'ट्रुथ एंड रीकन्सिलिऐशन कमिशन (टीआरसी) और 'कमिशन ऑफ इन्वेस्टीगेशन ऑन एन्फोर्स्ड डिसपिर्ड पर्सन्स (सीआईईडीपी) के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इन निकायों के प्रभावी कामकाज में देरी को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि आगे और विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नेपाल में माओवादी संघर्ष 1996 से 2006 तक चला था, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। संघर्ष का अंत 2006 में शांति समझौते के साथ हुआ, जिसके बाद नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

मुलाकात — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मैसूरु के जैन समाज के कांतिलाल चौहान, कांतिलाल पटावरी, गौतम सालेचा आदि ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के नए मैसूरु रेल मंडल प्रबंधक मुदित मित्तल से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने डीआरएम मित्तल से उत्तर भारत एवं राजस्थान की तरफ़ जाने वाली ट्रेनों की संख्या व फेरे बढ़ाने की मांग की, साथ ही यशवंतपुर से बाड़मेर तक की ट्रेन को वाया मैसूरु चलाने की मांग की। डीआरएम ने शीघ्र ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

अमेरिका में 1,000 से अधिक छात्रों के वीजा या देश में रहने की कानूनी अनुमति पर लगी रोक

वाशिंगटन/एपी। अमेरिका में 1,000 से अधिक विदेशी छात्रों के वीजा पर हाल के हफ्तों में रोक लगा दी गई है, जिसके बाद कई छात्रों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दायर करके दलील दी है कि सरकार ने उनसे अमेरिका में रहने की अनुमति अचानक वापस ले ली है। अमेरिका में रहने की कानूनी अनुमति वापस लेने के संघीय सरकार के फैसले के कारण सैकड़ों छात्रों के सामने हिरासत में लिये जाने और निर्वासित किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। इन छात्रों में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे निजी विश्वविद्यालयों, मैरीलैंड विश्वविद्यालय व ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे बड़े सार्वजनिक संस्थानों और कुछ छोटे महाविद्यालयों के छात्र शामिल हैं।

विश्वविद्यालय के बयानों, स्कूल अधिकारियों के साथ पत्राचार और अदालती रिकॉर्ड की 'एसोसिएटेड प्रेस' द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार, मार्च के अंत से अब तक 160 कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के कम से कम 1,024 छात्रों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं या अमेरिका में रहने की उनकी कानूनी अनुमति वापस ले ली गई है। गृह मंत्रालय के खिलाफ दायर मुकदमों में छात्रों ने तर्क दिया है कि सरकार के पास उनका वीजा रद्द करने या अमेरिका में रहने की कानूनी अनुमति वापस लेने का कोई उचित कारण नहीं है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों को इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए संदेश भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कॉलेजों का कहना है कि कुछ छात्रों को यातायात उल्लंघन जैसे मामूली उल्लंघनों के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें से कुछ घटनाएं बहुत पहले हुई हैं।

बांग्लादेश की पूर्व 'ब्यूटी क्वीन' पर सऊदी अरब के राजनयिक को ब्लैकमेल करने का आरोप

ढाका/भाषा। बांग्लादेश पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि ढाका में सऊदी अरब के पूर्व राजदूत को मोहपाश में फंसा कर 50 लाख अमेरिकी डॉलर ठगने की कोशिश के आरोप में एक पूर्व ब्यूटी क्वीन को हिरासत में लिया गया है।

वहीं पूर्व ब्यूटी क्वीन ने आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि राजनयिक उससे शादी करना चाहता था।

पुलिस ने ढाका की एक अदालत में दायर याचिका में कहा, ''मेघना आलम, उनके करीबी सहयोगी दीवान समीर और दो–तीन अन्य लोग विदेशी राजदूतों को खूबसूरत लड़कियों के साथ प्रेम जाल में फंसाने में संलिप्त थे।'' पुलिस ने हालांकि सऊदी राजनयिक या किसी अन्य दूत का नाम नहीं बताया लेकिन कहा कि उसे (महिला) ''देश की सुरक्षा में बाधा डालने और देश के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने'' के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

मॉडल एवं 'मिस अर्थ' रह चुकीं आलम (30) एक धर्मार्थ संस्था भी संचालित करती हैं और शुरुआत में उन्हें विवादास्पद विशेष शक्तियां अधिनियम के तहत बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया था। यह अधिनियम पुलिस को किसी संदिग्ध को कई महीनों तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। हालांकि, उनकी गिरफ़्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल रही और मानवाधिकार निगरानीकर्ताओं ने भी चिंता जताई। देश की अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नज़रुल ने कहा कि नौ अप्रैल को जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

वहीं मानवधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने पिछले हफ़्ते एक बयान में कहा, '' हम अधिकारियों से या तो मेघना पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले अपराध का आरोप लगाने या उन्हें रिहा करने का आग्रह करते हैं।'' पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद तालेबुर रहमान ने बताया कि अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया है। उस पर ब्लैकमेल के ज़रिए जबरन वसूली के प्रयास का प्राथमिक आरोप लगाया गया है।

बंगाली भाषा के समाचार पत्र 'प्रथम आलो' और अन्य मीडिया संस्थानों ने अपनी खबर में कहा कि आलम ने अदालत को बताया कि राजनयिक ने उससे संपर्क किया था और विवाह का प्रस्ताव दिया था।

सरकारी वकील उमर फारुक फारूकी ने संवाददाताओं को बताया कि आलम ने अदालत में दावा किया कि सऊदी राजनयिक ने उसे विवाह बंधन में बांधने का प्रस्ताव दिया था और बार–बार उसे फोन किया तथा संदेश भेजे, जबकि उसने कभी पहल नहीं की। आलम बृहस्पतिवार को अदालत की सुनवाई के दौरान बिना किसी वकील के उपस्थित हुई और उसने स्वयं अपनी दलीलें रखीं और अपनी गिरफ्तारी को रद्द करने का आग्रह किया।

दूसरा धर्म अपनाने वाले आदिवासियों से आरक्षण की सुविधा वापस ली जाए: चंपई सोरेन

बोकारो /भाषा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मांग की है कि दूसरा धर्म अपनाने वाले आदिवासियों से आरक्षण की सुविधा वापस ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय से बाहर शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं को आरक्षण सुविधा से बाहर किया जाना चाहिए। बोकारो जिले के बालीडीह जाहेरगढ़ में आयोजित 'सरहुल/बाहा' मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सोरेन ने दूसरा धर्म अपनाने वाले आदिवासियों या आदिवासी समुदाय से बाहर शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं को आरक्षण सुविधा दिए जाने का कड़ा विरोध किया।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.